RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

परिस्थितियां स्वाभाव बदल देती है, वरना इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है।

प्रेमानंद जी महाराज

वर्ष-08, अंक - 30 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 14 मई 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

आर्थिक संकट की आहट... या नाकामियों पर देशभक्ति का घूंघट...?

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर अपील को देशवासियों ने तन मन के साथ पूरा किया। चाहे वह सक्षम लोगों से की गई गैस सब्सिडी छोड़ने की हो, नोटबंदी पर 50 दिनों के संयम की हो, जनता कर्फ्यू में ताली और थाली बजाने की हो या कोरोना लॉकडाउन के दौरान दीपक जलाने की हो। हर अपील पर देशवासियों ने बिना कोई प्रश्न चिन्ह लगाए प्रधानमंत्री के कहे अनुसार कार्य किया। लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री द्वारा इराक, इजराइल और अमेरिका युद्ध के मद्देनजर की गई आम जनता से सात प्रकार की संयम की अपील को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर आम जनता के सामने आ रही है। कोई इसे पर उपदेश कुशल बहुतेरे बतला रहा है। तो कोई इसे सरकार की नाकामियों को आम जनता पर डालना बतला रहा है। यह सही है कि, युद्ध का असर पूरे विश्व पर पड़ना तय है ऐसे में कई लोग प्रधानमंत्री की इस अपील को देश के हित में बतला रहे हैं। लेकिन कई लोग सरकार पर सीधा सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि बचत की शुरुआत ऊपर से नीचे होना चाहिए ना कि नीचे से ऊपर। तात्पर्य यह है कि, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पहले आदर्श प्रस्तुत करें, उसके बाद आम जनता से अपील करें। वहीं कई लोगों का कहना है कि, युद्ध 70 से ज्यादा दिनों से चल रहा है ऐसे में यह अपील बहुत पहले ही की जानी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री को पांच राज्यों के चुनाव की चिंता थी और चुनाव निपटने के बाद यह अपील प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। इससे यह साबित होता है कि, प्रधानमंत्री जी को देश हित से ज्यादा चुनाव की चिंता थी।

क्या है प्रधानमंत्री की अपिल

वैश्विक संकट के बिच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आम जनता से 7 महत्वपूर्ण अपील की है जिसमें कहा गया है कि,

1.जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें।

2.एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा से बचे।

3.विदेशी उत्पादों का आयात व उपयोग कम करें, स्वदेशी अपनाएं।

4.रासायनिक उर्वरको पर निर्भरता कम करें और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े।

5.खाने के तेल के उपयोग में कटौती करें।

6.पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

7.एक वर्ष के लिए सोना खरीदने से बचें।

इन सात अपील के बाद देश भर में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कई लोगों का कहना है कि, प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद भाजपा शासित राज्यों में ही निगम मंडल के अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह में ही सैकड़ो गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। यही नहीं प्रधानमंत्री स्वयं रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील को पर उपदेश कुशल बहुतेरे कहावत को चरितार्थ कर रहा है। वहीं कई लोगों का कहना है वास्तव में आर्थिक संकट इतना गहराता जा रहा है तो इसकी शुरुआत सत्ता में बैठे शीर्ष राजनीतिज्ञयो द्वारा की जानी चाहिए। ताकि शीर्ष में बैठे लोग समाज में आदर्श प्रस्तुत करें और आम जनता उनका अनुसरण करें। वही सराफा से जुड़े लोगों का कहना है कि, प्रधानमंत्री की यह अपील उनका व्यापार चौपट कर सकती है, अगर ज्वेलर्स सोना नहीं बेचेंगे तो क्या झालमुडी बेचेंगे...?

बहरहाल प्रधानमंत्री की अपील वास्तव में एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रही है और इस संकट का समाधान शिवाय संयम के और कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का देश हित में की गई इस अपील का ,कई बुद्धिजीवी वर्ग समर्थन कर रहे हैं और देश के हित में इन नियमों का पालन करने की अपील आम जनता से कर रहे हैं। वही सत्ता शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों से भी उम्मीद कर रहे हैं कि, प्रधानमंत्री जी की सलाह पर विशेष ध्यान देकर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें।

आखिर दिशा की बैठक को चाय बिस्कुट की पार्टी क्यों कहा विधायक ने...

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति जिसे संक्षेप में दिशा भी कहते हैं की बैठक को लेकर जिले के एकमात्र कांग्रेसी विधायक भड़क गए और उन्होंने इसे केवल चाय बिस्कुट की पार्टी कहकर सरकारी दावों की पोल खोल दी। दरअसल में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक 3 महीने में एक बार किया जाना आवश्यक है। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा क्षेत्र के सांसद करते हैं और स्थानीय विधायक और पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इस समिति में जिला कलेक्टर पदेन सचिव होते हैं। इस बैठक का उद्देश्य कुशल और समयबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए संसद, राज्य विधानसभाओं स्थानीय सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों में सभी निर्वाचित सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय एवं निगरानी हेतु दिशा का गठन किया जाता है। यह सरकार की एक व्यापक पहन है जिसका उद्देश्य सहभागी शासन और विचार विमर्श अधारित लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। दिशा जिला स्तर पर सभी विकास गतिविधियों की त्रैमासिक समीक्षा की सुविधा प्रदान करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। दिशा बैठको में विचार विमर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने और प्रभावी कार्रवाई की मांग करने का अधिकार होगा। जिला कलेक्टर सदस्य सचिव है, जो बैठक बुलाने और प्रभावी एवं समय बद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया भड़क गए और उन्होंने इसे केवल चाय बिस्कुट की पार्टी करार दिया। क्योंकि विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया बार-बार दिशा बैठकों की तारीखों में बदलने को लेकर नाराज थे और वे इस वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे थे। उनका कहना था कि, एक बार तारीख तय करने के बाद उसमें बार-बार बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दिशा की बैठकों में पारित किए प्रस्तावो पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए।

एयर इंडिया ने कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अस्थायी रूप से कीं बंद

नई दिल्ली।

मध्य पूर्व में जारी तनाव और जेट ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच एयर इंडिया ने जून से आगामी तीन महीनों के लिए कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती करने का निर्णय लिया है। एयरलाइन ने दिल्ली से संचालित होने वाली कई प्रमुख विदेशी उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद या सीमित किया है।

जानकारी के अनुसार, शिकागो, नेवार्क, सिंगापुर और शंघाई जैसे प्रमुख गंतव्यों की उड़ानों में कमी की गई है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, पेरिस और टोरंटो के लिए भी उड़ानों की संख्या घटाई गई है। बताया जा रहा है कि एयरलाइन ने प्रतिदिन करीब 100 उड़ानों में कटौती की है।

एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन ने हाल ही में कहा था कि वैश्विक तनाव और ईंधन कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में कटौती जारी रखी जाएगी। बढ़ते आर्थिक दबाव और परिचालन चुनौतियों को देखते हुए एयरलाइन ने खर्च नियंत्रण और आंतरिक नियमों को और सख्त किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में नैतिक आचरण और नीतिगत उल्लंघनों के मामलों में एयर इंडिया ने 1,000 से अधिक कर्मचारियों को सेवा से हटाया है। इनमें कर्मचारी यात्रा सुविधा के दुरुपयोग, विमान से सामान की तस्करी तथा अतिरिक्त सामान को बिना शुल्क अनुमति देने जैसे मामले शामिल हैं।

एयर इंडिया समूह, जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल हैं, को मार्च 2026 तक समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 22 हजार करोड़ रुपए से अधिक के घाटे का अनुमान है।

ईंधन बचत अपील पर सांसद ढुलू महतो का अलग रुख

धनबाद। खाड़ी देशों से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित होने और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने की अपील की है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों से भी अपने काफिलों में वाहनों की संख्या घटाने का आग्रह किया है।प्रधानमंत्री की इस पहल के बाद कई राज्यों में नेताओं ने अपने काफिले छोटे करने शुरू कर दिए हैं। वहीं धनबाद में इस मुद्दे पर अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री की पहल का समर्थन करते हुए कहा कि वे स्वयं अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करेंगे।

हालांकि इसी दौरान मौजूद धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए काफिला कम करने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि धनबाद जैसे संवेदनशील क्षेत्र में उन्हें लगातार खतरा बना रहता है और सुरक्षा व्यवस्था में कमी उनके लिए जोखिम बढ़ा सकती है।

ढुलू महतो ने कहा कि, यदि सुरक्षा और वाहनों की संख्या घटाई गई तो माफिया तत्व उन पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के प्रभावशाली माफिया समूहों से उन्हें लगातार जान का खतरा बना हुआ है। सांसद ने कहा कि उनके लिए सुरक्षा काफिला सुविधा नहीं बल्कि आवश्यकता है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए ढुलू महतो को पहले से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर रखी है, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान तैनात रहते हैं। राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

सीबीआई निदेशक चयन प्रक्रिया, राहुल गांधी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नए सीबीआई निदेशक के चयन को लेकर असहमति जताई है। प्रधानमंत्री आवास पर मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद उन्होंने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए और विपक्ष की भूमिका को सीमित करने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और राहुल गांधी शामिल हुए। बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। इसके बाद राहुल गांधी ने सामाजिक माध्यम पर एक पत्र साझा कर कहा कि चयन प्रक्रिया को केवल औपचारिकता बनाकर रखा गया है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से 69 उम्मीदवारों की सूची तो उपलब्ध कराई गई, लेकिन उनसे संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और मूल्यांकन रिपोर्ट साझा नहीं की गईं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट और 360 डिग्री मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे विपक्ष की भूमिका प्रभावहीन हो जाती है।

उन्होंने अपने पत्र में कहा कि, चयन समिति में विपक्ष के नेता को शामिल करने का उद्देश्य प्रक्रिया को निष्पक्ष और संतुलित बनाए रखना है। यदि आवश्यक जानकारी ही उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो विपक्ष की भूमिका केवल औपचारिक रह जाएगी।

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसी का उपयोग राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों के खिलाफ किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना कानूनी आधार के जानकारी साझा करने से इनकार करना चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।

विधानसभा में मुख्यमंत्री ने हासिल किया विश्वास मत

चेन्नई।

तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरणों के बीच मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। तमिलगा वेत्री कझगम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने सदन में बहुमत साबित करते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली।

234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी, जबकि सरकार के पक्ष में 144 मत पड़े। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री विजय ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, वीसीके और आईयूएमएल सहित गठबंधन दलों का समर्थन मिला।

विश्वास मत के दौरान मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए। एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले गुट ने मुख्यमंत्री विजय का समर्थन करने की घोषणा की। बताया जा रहा है कि एआईएडीएमके के कई विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर सरकार के पक्ष में मतदान किया। वहीं भाजपा और पीएमके ने मतदान प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी।

चर्चा के दौरान वीसीके विधायक वन्नी अरसु ने नई सरकार के समक्ष कई नीतिगत मुद्दे उठाए। उन्होंने अंधविश्वास और ज्योतिष जैसी प्रथाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। साथ ही श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी के मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से स्कूली विद्यार्थियों के लिए संचालित नाश्ता योजना, को जारी रखा जाना चाहिए।

गौरतलब है कि चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री विजय की पार्टी पूर्ण बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गई थी। हालांकि गठबंधन सहयोगियों और विपक्ष के कुछ विधायकों के समर्थन से सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया।

ब्रिक्स 2026 : विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू

नई दिल्ली।

14 और 15 मई को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। भारत इस वर्ष 18 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी क्रम में आयोजित दो दिवसीय बैठक में सदस्य देशों और आमंत्रित राष्ट्रों के वरिष्ठ राजनयिक शामिल हो रहे हैं। बैठक का उद्देश्य वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करना है।

बैठक में ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से उप-विदेश मंत्री स्तर का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, जबकि चीन की ओर से विशेष प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहा है।

दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय संबंध मंत्री रोनाल्ड ओजी लामोला मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे, जबकि इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगिओनो बुधवार को राजधानी पहुंचे। ईरान ने भी अपने विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बैठक में शामिल होने की जानकारी दी है, हालांकि क्षेत्रीय परिस्थितियों के चलते उनकी यात्रा योजना में बदलाव संभव बताया जा रहा है।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भी जल्द नई दिल्ली पहुंचने की संभावना है। वे भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी व्यस्तता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह भारत में चीन के राजदूत शी फीहोंग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चीन ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का समर्थन भी व्यक्त किया है।

विदेश मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार, 14 मई को भारत मंडपम में विदेश मंत्रियों का आगमन हुआ, जिसके बाद पहले सत्र की शुरुआत की गई। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों से संयुक्त मुलाकात की। शाम को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की ओर से रात्रिभोज का आयोजन किया गया। 15 मई को तीसरे सत्र के साथ बैठक का समापन होगा।

वन विभाग की महज दो दिनों की कार्यवाही में लगभग 12 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण मुक्त

सवाल यह कि अब तक कहां सोया हुआ था वन विभाग का अमला और जिम्मेदार अधिकारी

इतनी बड़ी कार्यवाही के बाद एक भी अतिक्रमणकर्ता या भू-माफिया का नाम विभाग ने सार्वजनिक नहीं किया

माही की गूंज, झाबुआ।

पश्चिमी मध्यप्रदेश का आदिवासी बाहुल झाबुआ जिला यूं तो कई वजहों से जाना जाता रहा है। यहां की आबादी में बहुतायात हिस्सा ग्रामीण आदिवासी समाज का है। यहां की अधिकतर आबादी मजरों, टोलों और फलियों में बसती है। मगर बावजूद इसके इस आदिवासी समाज के लोग जल, जंगल और जमीन को अपना सबकुछ मानते है और इनकी पूजा करते है। कई शोधकर्ताओं के अनुसार आदिवासी समाज पूर्ण रूप से प्रकृति पूजन माना गया है। इस दृष्टिकोण से यह माना जा सकता है कि जल, जंगल और जमीन को आदिवासी समाज से कोई खतरा हो ही नहीं सकता। हालांकि आजादी के बाद से झाबुआ जिले के आदिवासी समाज की तस्वीर और तकदीर में कोई खास फर्क दिखाई नहीं दिया है। यह अब भी अल्प संसाधनों पर अपना जीवन यापन करते दिखाई देते है। मगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कागजों पर इस आदिवासी समाज में अमूल चूल परिवर्तन के दावे भरे पड़े है, लेकिन हकीकत इससे कोषो दूर है।

इस जिले में रहने वाले आदिवासी अधिकतर कब्जे की या पट्टे की भूमि को भी अपने जीवन यापन का सहारा बनाते है। कब्जे वाली जमीनों पर सरकारें इन्हे पट्टे भी उपलब्ध करा देती है। ताकि आदिवासी समाज इन भूमियों पर खेती कर अपना जीवन यापन कर सके और समृद्धि की ओर बढ़ सके। वर्तमान समय में हालातों में परिवर्तन देखने को मिल रहे है। इस आदिवासी बाहुल जिले में आदिवासियों की आड़ लेकर भू-माफिया सजगता दिखा रहे है और कई बेशकीमती सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहे है। भू-माफियाओं की इन हरकतों का शिकार वे आदिवासी भी हो रहे है जो जरूरत मंद है और भू-माफियाओं से अनभिज्ञ है। जब सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने और कब्जा मुक्त कराने की बात आती है तो वे आदिवासी सबसे पहले निशाने पर आता है, जो मजबूरी वश सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती करता है और अपना व परिवार का जीवन यापन करता है। जबकि इसके उलट भू-माफियाओं पर कार्रवाई या तो होती ही नही या फिर पंचनामों तक सिमट कर रह जाती है। इससे खुले रूप से नुकसान सिर्फ और सिर्फ गरीब आदिवासी का ही होता दिखाई देता है।

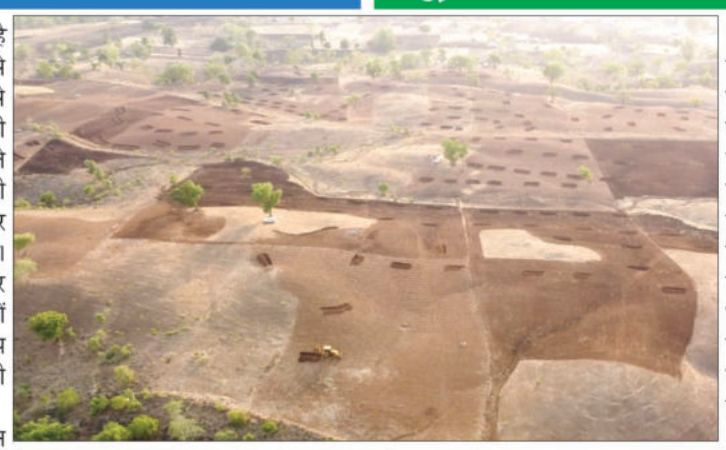

पिछले दो-तीन दिनों में जिले में वन विभाग ने एक ऐसा चमत्कार कर दिया जो वर्षों से नहीं हो पा रहा था। जिले के वन विभाग ने महज दो-तीन दिनों में ही जिले में लगभग 12 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। पहली कार्यवाही में जिले के पेटलावद क्षेत्र की रसोड़ी बीट में लगभग 3 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमणकार्ताओं से मुक्त कराई। तो वहीं दूसरी कार्यवाही में जिले के झाबुआ वन परिक्षेत्र की नवापाड़ बीट में 8.6 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। इस कार्यवाही को अंजाम देने के लिए वन विभाग का अमला अपने साथ बुलडोजर लेकर पहुंचा था। कार्यवाही में सात अस्थाई छोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि, वन विभाग के अमले की यह कार्यवाही भले ही बड़े भू-माफियाओं पर नहीं हुई है, लेकिन भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जबकि वन विभाग की कार्यवाही के अनुसार उन्होने वन भूमि से महज सात अस्थाई झोपड़ियों को तोड़ा है। इस कार्यवाही में वन विभाग ने किसी भी अवैध कब्जाधारी, अतिक्रमणकर्ता या भू-माफिया के नाम उजागर नही किए है।

हालांकि वन विभाग की यह कार्यवाही सराहनीय है। लेकिन सवाल यह है कि, इतनी ज्यादा और बड़ी जमीनों पर से अब तक कब्जे क्यों नहीं हटाए गए थे...? अगर इन जमीनों पर अवैध कब्जाधारियों और भू-माफियाओं का कब्जा था तो फिर वन विभाग ने उनके नाम उजागर क्यों नहीं किए...? सवाल यह भी है कि, क्या इन जमीनों पर गरीब आदिवासियों का कब्जा हटाकर वन विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा है...? सवाल यह भी कि जो सात अस्थाई झोपड़ियां वन विभाग ने हटाई है वहां कोई आवासीय था...? क्योंकि झाबुआ जिले की भोगोलिक स्थिति पर अगर नजर डाले तो आदिवासी समाज अपने मवेशी चराते हुए धूप, बारिश से बचने व छाव के लिए इस तरह की छोटी अस्थाई झोपड़ियां तो यूं ही बना लेता है। जिसका उपयोग वह कुछ समय करके यूं ही छोड़ देता है। यह और बात है कि, वन विभाग ने कार्यवाही के दौरान जिन सात अस्थाई झोपड़ियों को तोड़ा उनका कोई ब्योरा नही दिया गया। उन पर किस का कब्जा था यह भी नहीं बताया गया। हां इतना जरूर है कि विभाग के जारी वक्तव्यों में यह कहा गया कि, कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था। निर्धारित समय में कोई भी व्यक्ति भूमि पर अपना वैध अधिकार सिद्ध नहीं कर पाया। इसके बाद विभाग ने कानूनी प्रक्रिया के तहत बेदखली अभियान चलाया। मौके पर मौजूद लोगों को वन भूमि पर दोबारा अतिक्रमण नहीं करने और वन संपदा को नुकसान न पहुंचाने की सख्त चेतावनी भी दी गई।

वक्तव्यों में यह साफ हो जाता है कि वन विभाग की भूमि पर वहीं आसपास रहने वाले आदिवासियों ने अतिक्रमण किया था, जिसे वन विभाग ने मुक्त भी करवा लिया। लेकिन वन विभाग और अखबारों में छपी खबरें यह दर्शा रही है जैसे वन विभाग ने बड़े-बड़े माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों से अपनी जमीन छुड़वाई हो। कुल मिलाकर वन विभाग व उसमें बैठे जिम्मेदारों ने अपनी शेखी बघारते हुए आदिवासियों को भू-माफिया और अवैध कब्जेधारी बना दिया। वन विभाग की कार्रवाई कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन आदिवासियों पर कार्रवाई कर ढिंढोरा पीटना कहां तक उचित है। जबकि जिले में कई सरकारी जमीनों पर बड़े भू-माफियाओं का भी कब्जा है। वन विभाग यह स्पष्ट करे कि वह आदिवासियों से अपनी जमीन छुड़ा रहा है या फिर भू-माफियाओं से? क्योंकि जिले का आदिवासी जो जल, जंगल और जमीन को अपना सबकुछ मानता है और प्रकृति पूजक है वह अतिक्रमणकर्ता तो हो सकता है लेकिन भू-माफिया नही।

रही बात छुड़ाई गई जमीनों पर वन विभाग द्वारा कंटूर खुदाई की तो यह सराहनीय है, हालांकि कंटूर को भू-जल स्तर बढ़ाने का माध्यम बताना कहीं न कही संशय का विषय है। क्योंकि यह प्रमाणित नहीं है कि एक कंटूर से वर्षाकाल के दौरान कितना भू जल स्तर बढ़ता है। खोदे गए कंटूर का यह फायदा जरूर होगा कि जमीन में गड्ढे होने के कारण यहां कोई अतिक्रमण का कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा।

अब देखना यह है कि, जिले का वन विभाग इस कार्यवाही को कहां तक लेकर जाता है, और भू-माफियाओं से सरकारी जमीन को मुक्त करवाता है। या फिर अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत सिर्फ गरीब आदिवासियों को निशाना बनाते हुए उन्हे भू-माफिया और अवैध कब्जाधारी घोषित करता है।

हालांकि सवाल इसलिए भी कि, पिछले कई वर्षों में वन विभाग की इस तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अब अचानक वन विभाग की नींद खुली है। महज दो से तीन दिनों की कार्रवाई में लगभग 11.6 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराना भी लोगों के गले नहीं उतर रहा है। कार्रवाई के बाद किसी भी भू-माफिया या अवैध कब्जाधारी का नाम सार्वजनिक ना होना भी सवाल खड़े कर रहा है। पुरे जिले में सेकडो हैक्टयर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण है तो क्या जिले में सभी अतिक्रमण भूमि पर इसी तरह की कार्रवाई के साथ अतिक्रमण मुक्त किया जायगा...?

सफल हुई लोक अदालत

अभिभाषकों ओर कर्मचारियों के सहयोग से कई पक्षकारो को मिला लाभ

माही की गूंज, पेटलावद।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश एवं माननीय उच्च न्यायालय के नेतृत्व में मप्र की समस्त अदालतों में 9 मई को नैशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में प्रधान न्यायाधीश झाबुआ श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में झाबुआ ,थांदला सहित पेटलावद के समस्त न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित हुई इस लोक अदालत का शुभारंभ अपर सत्र न्यायधीश ओमप्रकाश वोहरा ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर दीप प्रज्वलन कर किया, शुभारंभ के अवसर पर सिविल जज वरिष्ठ खंड श्री सोहनलाल भगोरा, श्रीमती नेहा मौर्य सोलंकी ओर सिविल जज वर्ग 2 श्री प्रियम कुमार सक्सेना की गरिमामय उपस्थिति में लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। ओर तत्पश्चात अधिवक्ताओं ओर न्यायाधीशगणों की एक बैठक का भी आयोजन हुआ। लोक अदालत में चारों कोर्टों में अभिभाषकों के सहयोग ओर समझाइश के आधार पर कई सिविल, अपराधिक, क्लेम प्रकरणों का निपटारा करते हुए कई पक्षकारो को लाभान्वित किया गया । नगर परिषद,विद्युत मंडल ओर भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि बैंकों के भी कई लोन वसूली ओर बिल का भुगतान करते हुए मामले का निराकरण किया गया। वही वर्षों पुराने कई मामलों का भी निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में अभिभाषक संघ पेटलावद के अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारियों व समस्त अधिवक्ताओं ओर न्यायालयीन कर्मचारियों का सहयोग रहा।

पुराने अस्पताल परिसर में मिला पान व्यवसायी का शव, सुसाइड नोट और सल्फास डिब्बी बरामद

माही की गूंज ,पेटलावद।

नगर के पुराने अस्पताल परिसर में रविवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब यहाँ एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। मृतक की पहचान कुम्हार मोहल्ला निवासी मंगतू पिता शंकरलाल गवली के रूप में हुई है, जो पुराने बस स्टैंड पर पान की दुकान संचालित करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया।

मृतक के पास से पुलिस को सल्फास की एक खाली डिब्बी और एक कागज (सुसाइड नोट) बरामद हुआ है, जिसे जांच में शामिल किया गया है। मौके पर मृतक की पेंट भी शरीर से निकली हुई हालत में मिली, जिससे मामला पेचीदा नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार, मंगतू पिछले कुछ समय से पारिवारिक जमीन विवाद के चलते तनाव में था। कुछ माह पूर्व उस पर तलवारबाजी का एक प्रकरण भी दर्ज हुआ था, जिसके बाद से ही वह अपने घर न जाकर संतोष राठौड़ नामक व्यक्ति के साथ एक कमरे पर रह रहा था।

शनिवार शाम करीब 4 बजे मंगतू यह कहकर निकला था कि वह रतलाम जा रहा है, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। रविवार सुबह मेडिकल पर काम करने वाले राहुल राठौड़ ने सबसे पहले पुराने अस्पताल के कमरे में शव देखा और मित्र भागीरथ यादव को सूचना दी। टीआई निर्भयसिंह भूरिया ने बताया कि पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। सुसाइड नोट और सल्फास की मौजूदगी आत्महत्या की ओर इशारा कर रही है, लेकिन जमीन विवाद और पिछली रंजिशों को देखते हुए पुलिस अन्य संभावनाओं को भी तलाश रही है। मृतक अपने पीछे पत्नी, बेटा और बेटियों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गया है।

राम कथा से नैतिक मूल्यों की सीख देती है

माही की गूंज, सारंगी।

श्री खेड़ापति हनुमान जी मंदिर परिसर में चल रही संगीत मय राम कथा में सप्तम दिवस श्रद्धालु भक्ति रस में डूब कर कथा का श्रवण किया। राम कथा इन दीनों श्रद्धा और आध्यात्मिकता का केंद्र बनी हुई है। कथा वाचक पंडित महावीर शर्मा ने प्रवचन में जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि, कथा के दौरान मन ,वचन और कर्म पूर्ण रूप से भगवान में लीन रहे तभी कथा का वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। कथा के दौरान भजन गायको द्वारा प्रस्तुत भजनों ने वातावरण को भक्ति मय बना दीया। श्रद्धालु भाव विभोर होकर भजनों पर झुमते नजर आए। कथा स्थल पर विभिन्न क्षेत्र के गणमान्य नागरिको सहित सैकड़ो की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथावाचक पंडित महावीर शर्मा ने श्रद्धालुओं को राम भक्ति और कथा श्रवण का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। राम कथा व्यक्ति को धैर्य , मर्यादा और नैतिक मूल्यों की सीख देती है। राम नाम का स्मरण व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। राम कथा का आयोजन नानालाल जोशी एवं जोशी परिवार की ओर से किया जा रहा है प्रतिदिन महा आरती एवं प्रसादी का वितरण अलग-अलग भक्तों द्वारा किया जा रहा है। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं।

शराब जप्त लेकिन असल आरोपी तक नही पहुंचेगी आबकारी

माही की गूंज, झाबुआ।

मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने 715 पेटी अवैध शराब की परिवहन होते हुए जप्त की। जिसकी अनुमानित कीमत 27 लाख रुपए बताई जा रही है।

जानकारीनुसार ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचएफ 4547 में मवेशियों को खिलाने वाले भूसो से भरे कट्टें की कवरिंग में अवैध शराब झाबुआ से राणापुर व राणापुर से आलीराजपुर की ओर जाने वाले ट्रक में अवैध शराब परिवहन की सूचना झाबुआ आबकारी के विभाग के अधिकारियों को मिली। जिस पर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर विकास वर्मा, अकलेश सोलंकी एवं स्टाफ ने झाबुआ-राणापुर मार्ग पर उक्त वाहन की चेकिंग करने पर ट्रक में ऊपर भूसे से भरे कट्टे कवरिंग में जा रहे थे। जिन्हें हटाने पर अंदर शराब की 715 पेटियां अवैध मिली।

आबकारी विभाग ने ट्रक के साथ शराब जप्त कर ट्रक चालक आलीराजपुर निवासी बदरुद्दीन अनवर खान की गिरफ्तारी लेकर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। यह मुखबरी के आधार पर आबकारी विभाग की सफलता जरूर कहीं जा सकती है।

लेकिन शराब के संबंध में जानकारी रखने वाले बताते हैं कि, यह शराब झाबुआ जिले के शराब ठेकेदार की नहीं होने के चलते शराब आबकारी विभाग ने जप्त की है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि, उक्त मुखबारी स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से आबकारी को लगी और उक्त शराब जप्ती की कार्यवाही की गई ।

यहां आबकारी विभाग के अधिकारी भले ही उक्त शराब जप्ती के साथ मीडिया के माध्यम से अपनी वाहवाही ट्रक चालक की गिरफ्तारी के साथ लूट रही है। लेकिन असल आरोपी तक आबकारी विभाग कभी भी उक्त मामले में भी नहीं पहुंचेगी।

बता दे कि, शराब ठेको की दुकान पर ड्यूटी के साथ जो शराब आती है वह एमपी एग्रो डिपो इंदौर से आती है। इसके अलावा जो अवैध शराब आती है वो डिपो से नहीं आकर सीधे शराब फैक्ट्रीयों से भरकर अवैध रूप से आती है। यहां खास बात यह है कि, प्रत्येक शराब फैक्ट्रीयो में आबकारी स्पेक्टर तैनात रहते हैं और शराब फैक्ट्री में बनी शराब वैध रूप से ही परमिट के माध्यम से राज्य में जाने हेतु डिपो पर व अन्य राज्य में जाने हेतु परमिट के साथ सीधे फैक्ट्री से भरकर जा सकती है। जिसका एक-एक बोटल का हिसाब आवक-जावक का आबकारी विभाग के पदस्थ इंस्पेक्टर के पास होना रहता है। और इंस्पेक्टर की निगरानी में ही फैक्ट्री के गेट से बाहर शराब जा सकती है।

ऐसे में जो आबकारी विभाग उक्त शराब जप्ती के साथ वाहवाही लूट रही है जिसपर माही की गूंज दावा कर रहा है कि, यह आबकारी विभाग असल आरोपी तक नहीं पहुंच पाएगी और यह हमारा दावा सटीक व सत्य भी है। क्योंकि आबकारी विभाग को असल आरोपी तक पहुंचना है तो चालक के बयान एवं मोबाइल जप्ती के साथ। उक्त शराब को सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ फैक्ट्री से आबकारी इंस्पेक्टर की उपस्थिति में निकली उक्त शराब मामले में आबकारी स्पेक्टर के साथ फैक्ट्री मालिक तक असल आरोपी बनते हैं। लेकिन शराब जप्ती की वाहवाही लूटने वाले आबकारी विभाग के अधिकारी असल आरोपीयो तक नहीं पहुंचेंगे और फैक्ट्री तक भी जाच के नाम पर जाएंगे और अपना गांधी छाप अर्थ लाभ लेकर हमेशा की तरह कार्यवाही की इतिश्री कर दी जाएगी।

खबर का असरः बामनिया - रायपुरिया मार्ग पर मरम्मत का कार्य शुरू, साइडे भराव को लेकर संशय जारी

माही की गूंज, पेटलावद।

पिछले अंक में प्रमुखता से प्रकाशित बामनिया-पेटलावद- रायपुरिया मार्ग पर चल रहे साइडे भराव के कार्य में लापरवाही ओर सड़क पर कई हिस्सों में हो रहे गड्ढों को लेकर खबर प्रकाशित की थी। साइडे भराव में लापरवाही ओर बारिश के पहले गड्ढों को भी नहीं भरा गया तो ये मामूली गड्ढे जान लेवा रूप ले लेगे इस पर प्रमुखता से संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षक किया गया था। गूंज की खबर के बाद मार्ग पर गड्ढे भर डामर की नई कोटिंग करने का कार्य शुरू किया गया है। हालांकि कार्य एक या दो दिन बामनिया की ओर से शुरू हुआ ओर फिर एक दो दिन के बाद कार्य रुक गया है। लेकिन सड़क पर कार्य करने वाली भारी मशीन सड़क के पास ही खड़े होने से उम्मीद है कि, पूरे मार्ग की मरम्मत कर मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी।

साइडे भराव को लेकर संशय जारी

सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू तो हुआ लेकिन साइडे भराव को लेकर अभी भी संशय है, सड़क के दोनों ओर साइड ऊंची हो चुकी है जिससे सड़क से साइड पट्टी पर उतरे वाहनों को सड़क पर चढ़ने में दुर्घटना का भय रहता है खास कर छोटे ओर दुपहिया वाहन छोटी मोटी दुर्घटना का शिकार हो जाते है। मार्ग पर साइडे भराव का कार्य तो शुरू हुआ लेकिन कुछ एक स्थानों पर भराव किया गया बाकी जगहों को ऐसे ही छोड़ दिया । जहां भराव किया गया वहा ठेकेदार ओर जिम्मेदार विभाग द्वारा मोहर्रम बिछवाने की जगह सड़क के आसपास से मिट्टी उठा कर भराव किया गया जो बारिश में कीचड़ का रूप ले कर दुर्घटनाओं का कारण बनेगा। फिलहाल साइड भराव का कार्य बंद है,मार्ग की नई डामर कोटिंग के बाद सड़क थोड़ी ओर ऊंची होगी और साइड भराव जरूरी हो जाएगा।

शराब ठेकेदारों की मनमानी जारी, आबकारी विभाग की भूमिका दलाल जैसी

बड़ा सवाल, क्या कलेक्टर साहब करेंगे कार्रवाई...?

माही की गूंज, पेटलावद।

शराब दुकानों से न केवल सरकार को बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी नुमाइंदों को भी भारी लाभ अर्जित हो रहा है। जिसके चलते शराब ठेकेदार को सम्पूर्ण संरक्षण दिया जा रहा है। खास कर आबकारी विभाग जो इस व्यापार की देख-रेख सहित होने वाले अवैध शराब के व्यापार पर लगाम लगाने के लिए है। वर्तमान में आबकारी विभाग की भूमिका शराब ठेकेदार के दलाल जैसी हो गई है जहां शराब को लेकर कोई भी मामला हो विभाग, ठेकेदार के इशारों पर मुजरा करने तैयार रहता है। विगत दिनों करवड़ की शराब दुकान पर प्रिंट रेट से भी अधिक मूल्य पर शराब बेचने के मामला सामने आया था। सब कुछ मय प्रमाण बकायदा बियर के टीन पर लिखी अधिकतम कीमत से 35 रुपए अधिक वसूले गए, आन लाइन भुगतान के बाद मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन तक जाती है। आबकारी विभाग कार्रवाई करने की बजाए ठेकेदार के माध्यम से ही शिकायतकर्ता से मामला निपटाने की भटइ तक करता है। जब शिकायकर्ता, शिकायत वापस नहीं लेता तो आबकारी विभाग चुप चाप अपने ऑफिस में घुस कर बैठ जाता है। उधर कार्रवाई नहीं होने के बाद शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन करके शिकायत अपडेट कर दूसरे लेवल तक पहुंचा दी। फिर भी दलाली में लगे विभाग के जिम्मेदारो की नींद नहीं खुली। मामले में कार्रवाई अभी भी लंबित है और करवड़ की ही देशी कम्पोजिट शराब दुकान से एक ओर मामला सामने आ गया।

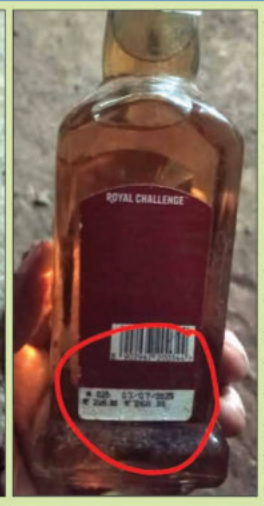

10 माह पुराना शराब क्वार्टर थमाया

करवड़ शराब की दुकान पर शराब लेने गए व्यक्ति ने रॉयल चेलेंज का क्वार्टर 250 रुपए में खरीदा और जब उस पर लिखे मूल्य को देखने के लिए क्वॉटर देखा तो उस पर लिखी तारीख पर नजर पड़ी। तो उस पर लिखी तारीख 3जुलाई2025 अंकित थी। शराब खरीदार ने उक्त क्वॉटर का फोटो दोनों ओर से हमको भेज कर इसकी जानकारी दी। हालाकी शराब एक्सपाइरी नही है पर सवाल यहा यह की जिले में शराब की बिक्री इतनी मात्रा में होती है कि, शराब के ट्रक आते ही बिक जाती है ऐसे में 10 माह पुरानी शराब का मिलना कई सवालो को खड़ा करता है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह भी उठता है कि, एक अप्रैल से नए वर्ष के लिए टेंडर हुए हैं और मार्च के अंत में जो भी माल बचा होगा उसकी सूची तैयार कर माल अपने कब्जे में लिया होगा, जिसे नए ठेके होने के बाद नई खरीदी के साथ माल ठेकेदार को आबकारी विभाग ने दिया होगा। अब वर्ष 2025 वो भी सातवें महीने की शराब की बोतले आबकारी विभाग ने अपने कब्जे में ली या बिना रिकॉड पर लिए माल ठेकेदार को ही बेचने के लिए दिया गया। या नए ठेके होने के बाद ये शराब ठेकेदार अपने अवैध भंडारण से शराब के वैध काउंटर से बेच कर सरकार को राजस्व का चुना लगा रहा है?

आबकारी विभाग की मिलीभगत के चलते चल रहा अवैध शराब का व्यापार

अवैध शराब का व्यापार पूरे क्षेत्र में कुकुरमुत्ते की तरह फैल गया है, मुख्य मार्गो पर हर थोड़ी दूर पर खुले ढाबों पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है ओर ये अवैध रूप से शराब ठेकेदार की दुकानों से यहां तक पहुंच रही है। कार्रवाई के नाम पर खुद आबकारी अवैध शराब विक्रेताओं से टारगेट के नाम पर 15 से 20 क्वाटर का केश बनाती है और कुछ यही हाल पुलिस का भी है। कहा जाए तो अवैध शराब का व्यापार आबकारी ओर पुलिस की मिलीभगत से ही चल रहा है।

एसपी ,कलेक्टर ले संज्ञान

यदा कदा कही पुलिस व आबकारी द्वारा अवैध शराब पकड़ी जाती है तो जारी प्रेस नोट में जिला कलेक्टर ओर पुलिस अधीक्षक के निशा निर्देशन में शराब पकड़ा जाना बताया जाता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता । सिर्फ बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए ऐसा किया जाता है। नवागत कलेक्टर और नवागत पुलिस अधीक्षक अगर इस अवैध शराब व्यवसाय का संज्ञान ले तो उन्हें पता लगेगा कि, नशे के नाम पर कैसे हर थोड़ी दूर पर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है ओर शराब ठेकेदारो द्वारा वैध शराब की आड़ में उससे कई गुना अधिक अवैध शराब बेची जा रही हैं। अवैध रूप से पुरानी तारीख की शराब ओर प्रिंट मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेची जा रही है।

आचार्य श्री विश्वरत्न सागर महाराज का होगा भव्य मंगल प्रवेश

माही की गूंज, पेटलावद।

श्री नाकोड़ा भैरव देव के परम उपासक गादीपति सुमित पिपाड़ा के आदेशानुसार विश्व की दूसरी मेवानगरी का निर्माण झाबुआ जिले के पेटलावद में होने जा रहा है। ज्ञात हो कि विश्व की प्रथम मेवानगरी राजस्थान में नाकोड़ा जी नाम से प्रसिद्ध है। मध्यप्रदेश की प्रथम मेवानगरी के रूप में विकसित होने जा रहे मेवानगर पेटलावद में 16 एवं 17 मई को भव्य धार्मिक आयोजन आयोजित होंगे। यह आयोजन मालव भूषण आचार्य श्री नवरत्न सागर जी महाराज साहब के सुशिष्य वर्तमान आचार्य श्री विश्वरत्न सागर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में संपन्न होंगे।

कल होगा मंगल प्रवेश

15 मई को आचार्य श्री विश्वरत्न सागर जी महाराज साहब आदि ठाणा का मेवानगर पेटलावद में भव्य मंगल प्रवेश होगा। इस अवसर पर श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव ट्रस्ट मंडल, कार्यकारिणी एवं समाजजन द्वारा आचार्य श्री की आगवानी की जाएगी। इसके पश्चात 16 मई को रात्रि 8 बजे उदय गार्डन, पेटलावद परिसर में सुप्रसिद्ध भजन गायक द्वारा श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव भक्ति संध्या का आयोजन किया जाएगा।गादीपति सुमित पिपाड़ा के आदेशानुसार 17 मई को दामोदर कॉलोनी स्थित श्री नाकोड़ा भैरव दरबार से आचार्य श्री विश्वरत्न सागर जी महाराज की पावन निश्रा में 11 अश्व, बैंड-बाजों एवं ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य वरघोड़ा प्रातः 7 बजे प्रारंभ होगा। यह वरघोड़ा नया बस स्टैंड होते हुए दादा द्वारा चयनित पावन भूमि तक पहुंचेगा। जहां दादा के आदेशानुसार 27 शिलाओं के साथ श्री पार्श्वनाथ भगवान, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री नाकोड़ा काला भैरव देव, शासन देवी श्री अछुपता माताजी एवं क्षेत्रपाल राजा की मुख्य शिलाओं पर संगीतकारों द्वारा चढ़ावे बोले जाएंगे। तत्पश्चात विधिकारकों द्वारा समस्त शिलाओं का विधिवत पूजन कराया जाएगा।

महामांगलिक का होगा आयोजन

गादिया रेस्टोरेंट गली स्थित उदय गार्डन, पेटलावद में शुभ मुहूर्त दोपहर 12रू39 बजे आचार्य श्री विश्वरत्न सागर जी महाराज साहब द्वारा महामांगलिक फरमाया जाएगा। मान्यता है कि इस चमत्कारिक महामांगलिक का श्रवण करने मात्र से आधी-व्याधि, दुःख एवं संकटों का निवारण होता है।

ट्रस्ट मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महामांगलिक में झाबुआ, रतलाम, नागदा, आलोट, राजगढ़, इंदौर, आगर, शाजापुर एवं उज्जैन सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में गुरु भक्तों के शामिल होने की संभावना है। श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव ट्रस्ट मंडल ने सकल श्रीसंघ एवं समाजजनों से आयोजन में सपरिवार अधिक से अधिक संख्या में पधारकर आयोजन को सफल बनाने एवं मेवानगर निर्माण में तन-मन-धन से सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

प्रजापति समाज ने श्री शीतला माता का सहस्त्र घटा महाअभिषेक संपन्न

माही की गूंज, पेटलावद।

स्थानीय प्रजापति समाज द्वारा रविवार को नगर के आराध्य स्थल श्री शीतला माता मंदिर पर भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। भीषण गर्मी के बीच माता रानी को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष होने वाला पारंपरिक श्री सहस्त्र घटा महाअभिषेक पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया।

यह विशेष आयोजन वर्ष में केवल एक बार ग्रीष्म ऋतु में आयोजित किया जाता है, जिसमें माता जी जल से अभिषेक करने की परंपरा है। इस वर्ष के कार्यक्रम में मुख्य यजमान प्रकाश प्रजापति रहे, जिन्होंने सपरिवार विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर महाअभिषेक की शुरुआत की। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच माता जी का जल एवं पंचामृत से अभिषेक किया गया। मान्यता है कि इस अभिषेक से न केवल माता रानी प्रसन्न होती हैं, बल्कि क्षेत्र में सुख-शांति और ठंडक बनी रहती है। अभिषेक के पश्चात माता जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया और महाआरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। इस अवसर पर प्रजापति समाज के वरिष्ठ जन एवं बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही।

मार्मिक दृश्यः सवा वर्ष पत्नी की मृत्यु के बाद भी पति को नहीं मिला अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण-पत्र, कलेक्टर से लगाई गुहार

माही की गूंज, झाबुआ।

झाबुआ जिले के प्रशासनिक नुमाइंदों की मनमानी, भ्रष्टाचार व अनदेखी की अनेकों मिसाले दी जा सकती है। वही इन मनमानी, भ्रष्टाचार व अनियमित्ताओ को दूर करने के लिये जनसुनवाई चालू की गई। लेकिन जिला प्रशासन, जनसुनवाई में आई समस्याओं के समस्त निराकरणो का हवाला देकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से मंचों पर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित होना व करवाने का दावा मंत्री जी प्रशासनिक झूठे दावों पर कर चुके हैं। लेकिन जिले की हकीकत यह है कि, यहां एक पत्नी की मृत्यु होने के बाद सवा वर्ष बीत जाने के बाद तक भी उसे मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया। यहा सब से बडी बात यह भी सामने आ रही है कि, पेटलावद जनपद क्षेत्र की जिस उमरकोट पंचायत ने रिश्वत नही मिलने पर मृत्यु प्रमाण-पत्र सवा वर्ष तक नही दिया इस पंचायत की सरपंच पुर्व सांसद गुमानसिंह के भाई गजराज सिंह की पत्नि है। यानी भाजपा के पुर्व सांसद की भाभी सरपंच है तो वही पुर्व सांसद का भाई जिस पंचायत को संभाल रहा है वहा यह मामला सामने आया है। ऐसे में सरकार व प्रशासन इसका क्या जवाब दे यह हमें नही पता।

लेकिन जिले में पुलिस प्रशासन पर कहावत है कि, पुलिस अपनी कार्रवाई के दौरान मरे हुए व्यक्ति के कफन के पैसे लेने में भी कोई संकोच नहीं करती है। पर यहां पुलिस प्रशासन का मामला नहीं पर यह झाबुआ जिला है यहां सारी मानवीय संवेदनाएं अर्थलाभ के चलते पैरों तले कुचली जाती है। इसलिए यह जिला मध्य प्रदेश में मनमानी, भ्रष्टाचार व अनियमिताओं के नए-नए आयाम गढने में अपनी महारत हासिल करते रहता है। जिसका एक उदाहरण झाबुआ कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान सामने आया। जिसमें ग्राम उमरकोट निवासी बद्रीनारायण मारवाड़ी अपने एक हाथ में अपनी पत्नी जिसकी मृत्यु 11 फरवरी 2025 यानी सवा वर्ष पूर्ण हो गई थी उसका फोटो व दूसरे हाथ में ग्राम पंचायत द्वारा पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्रमाणिक प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर एक शिकायत पत्र लेकर कलेक्टर के सामने जनसुनवाई में पहुंचा। यह सभी मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करने वाला मार्मिक दृश्य कलेक्टर कार्यालय में देखा गया। उक्त दृश्य को देखकर हर कोई चौक गया और इस दृश्य ने यह भी दर्शा दिया कि, इस जिले में भ्रष्टाचार किस कदर चरम पर है। जहां एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी रिश्वत ली जाती है। और अगर रिश्वत नहीं मिलती है तो सालों तक मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनना नामुमकिन हो जाता है। शिकायतकर्ता पति बद्रीनारायण ने बताया कि, पंचायत में इन सवा सालों में कई बार प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत से लेने गया लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। तथा प्रमाण पत्र देने के नाम पर रिश्वत मांगी गई।

सिस्टम की हकीकत कलेक्टर के सामने बया करते हुए एक हाथ में सवा वर्ष पुर्व मृत पत्नि रमिला बाई का फोटो तो दुसरे हाथ में पति का शिकायत पत्र।

बता दे कि, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन बनाया जाता है जिसे बनाने हेतु लोकसेवा केंद्र में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। आवेदन में ग्राम पंचायत, पटवारी, आंगनबाड़ी आदि जगहों के प्रमाणित जन्म व मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। जिसके बाद उक्त प्रमाण पत्र लोकसेवा केंद्र में तहसीलदार के नाम पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। जिसके बाद जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनते हैं।

ऐसे में एक पति की, अपनी पत्नी की मृत्यु के सवा वर्ष बाद तक पंचायत द्वारा मृत्यु का प्रमाणित प्रमाण पत्र रिश्वत नहीं मिलने के कारण जारी नहीं करना पूरे सिस्टम की पोल खोलता है। और नवागत कलेक्टर डॉ. योगेश भरसट के लिये भी यह चुनौती है कि, जिले में एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिये सवा वर्ष बाद पति को अपनी मृत पत्नी का फोटो हाथ में लेकर कलेक्टर कार्यालय में आना पड़ा...? यह पूरे सिस्टम की ही कमी दर्शाता है। ऐसे में कलेक्टर को जमीनी स्तर पर अपने सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है।

घुसपैठियों को बाहर निकालने के अपने वचन को निभाकर भाजपा जनता के मन में बसने के पूर्ण करें प्रयत्न

माही की गूंज, झाबुआ।

समय के चक्र को न तो कोई रोक सका है और न ही कोई उसे बदल सकता है, क्योंकि समय पीछे मुड़ कर देखता नहीं अपितु मानव मस्तिष्क में इतिहास के किस्से कहानियों और सत्य घटनाओं की स्मृति बना देता है।

2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। इस ऐतिहासिक विजय के पीछे भी इतिहास का एक चक्र घुमा है। टीएमसी, भाजपा की जीत और अपनी हार पर अनेक आरोप भाजपा पर लगा रही है। वहीं हारी हुई ममता बनर्जी अब पुराने उन साथियों को मिलकर साथ चलने और भाजपा के विरोध में सशक्त लामबंध होने के लिए आह्वान कर रही है, जिसमें कुछ लोकल पार्टिया, वामपंथी दल, कांग्रेस जैसी पार्टिया शामिल है।

टीएमसी की हार का कारण ममता बनर्जी का शासन जो कुशासन का पर्याय बन गया था। बीते 15 वर्षो से सत्ता पर आसीन ममता ने मुस्लीम तुष्टीकरण की सीमा पार कर दी। अपने वचनों को पुरा नहीं करना भी और इसी कारण हिंदुओं ने अपनी पीड़ा को दर्शाते हुए भाजपा के समर्थन में स्वयं को खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी की लोकप्रियता में कमी, फिर उनके नेताओं द्वारा जनता से अवैध वसुली और लोगों की संपत्ती पर कब्जा, पुरे पश्चिम बंगाल में महिला असुरक्षा का मुद्दा भी शिर्ष पर रहा। इस तरह टीएमसी के प्रति सत्ता विरोधी माहौल गहराता गया और जनता ने अपनी शक्ती का प्रदर्शन कर दिया। ममता बनर्जी अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारते हुए पश्चिम बंगाल में इस बात को फैला रही है कि उसे किसी षड़यंत्र रचकर हराया गया है।

स्वतंत्रता के पश्चात बंगाल में शुरुआती दशक में कांग्रेस का शासन रहा उसके बाद वामदल ने तीन दशक से अधिक समय तक बंगाल में शासन किया। सत्ता का लोभी बनता वाम दल ने जनता पर अत्याचार कर अपने शासन को कुशासन में बदल दिया, तब बंगाल की जनता ने परिवर्तन की चाह के साथ वाम दल को चुनौती देने वाली ममता की पार्टी का पक्ष लिया और बंगाल से वामदल के शासन को उखाड़ फैका। परंतु धीरे-धीरे बंगाल में फिर से वही होने लगा जो वामदल के समय होने लगा था। वामदलों के तौर तरिके टीएमसी पार्टी अपना रही थी, क्योंकि वाम दलों के नेता और कार्यकर्ता टीएमसी पार्टी में आकर बस गए थे।

ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध करती थी वही टीएमसी पार्टी सत्ता पाने और उसे यथावत रखने के लिए घुसपैठियों का समर्थन करने के साथ उनका बचाव भी करने लगी और साथ ही सच से मुंह मोड़ते हुए बड़े-बड़े मंचों से बयान देती रही कि, बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ नहीं होती है।

जो पार्टी सत्ता से पहले बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का विरोध करती थी तब वह सबूत के साथ कहती थी कि, घुसपैठियें बंगाल में घुस रहे हैं, और सत्ता में आने के लिए जनता को वचन देती थी कि, टीएमसी के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालेगे और घुसपैठियों को किसी भी किमत पर बंगाल में घुसने नहीं देगे। वही टीएमसी पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों को सत्ता के लोभ में स्वीकार करने लगी। बंगाल की जनता ने प्रतिज्ञा को पूरा होने की प्रतिक्षा की परंतु अपनी आशाओं पर पानी फेरते हुए देख जनता ने निर्णय लिया उस ममता के लिए जिसने घुसपैठियों को भगाने के बजाय आश्रय दे दिया। ममता बनर्जी यह क्यों भूल गई कि, वामदलों को भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोटबैंक बनाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसी तर्ज पर 2026 में वैसी ही कीमत ममता बनर्जी को चुकानी पड़ी। इतिहास से सीखते हुए भाजपा ने इस चुनावी दंगल में घुसपैठियों को भगाने का केसरी दावं लगाया और टीएमसी को चीत्त कर दिया।

भारत के प्रधानमंत्री, और गृहमंत्री दोनों ने चुनावी दंगल में घुसपैठियों को देश से बाहर निकलने की बात पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि, घुसपैठ केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि यह राज्य की अस्मिता की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सत्ता में आने पर भाजपा, घुसपैठियों को बाहर करेगी। देश को पता लगना चाहिए कि, कांग्रेस ने देश की भूमि पर घुसपैठियों द्वारा अतिक्रमण होने दिया। असम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है, इसीलिए घुसपैठियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। राज्यों में भाजपा की सत्ता आ जाएगी तब असम, त्रिपुरा और बंगाल के सभी घुसपैठियों को बाहर निकाल कर उनके देश भेज दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने घुसपैठियों के मुद्दे को बार-बार उठाया, बिहार, झारखंड में भी घुसपैठियों का मुद्दा था तब क्या उससे यह प्रतित हो रहा है था कि, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना पार्टियों के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बंगाल में गृहमंत्री ने कहा था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन-चुन कर बाहर निकालेगी। उससे पहले असम में कहा था कि, भाजपा की तीसरी बार सरकार बन गई तब घुसपैठियों को निकलने में देर नहीं होगी। अब सरकार बन गई, असम में भी और बंगाल में भी। अब घुसपैठियों को राज्यों से बाहर निकालने के लिए सरकार को कोई प्रभावी कार्य शीघ्र अतिशीघ्र शुरु करना होगा।

रिकेश बैरागी

घुसपैठिए देश के लिए कितने हानिकारक है यह जानते हुए भी सरकार को इस विषय पर गंभीर होकर जल्द ही योजनागत क्रिया को मुर्त रुप देने में समर्थता दिखानी होगी। क्योंकि घुसपैठिए देश के संसाधनों पर बोझ होने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, और जिन लोगों से राष्ट्र को भयंकर खतरा है उनके लिए सरकार के अभियान की गति में उत्साह नहीं दिखाई देगी तब भाजपा के लिए यह कितनी चिंता का विषय हो सकता है उसका इतिहास से आंकलन कर लेना चाहिए।

बहरहाल घुसपैठियें सरलता से देश में घुस कर अपना ठीकाना बनाने में सफल हो जाते हैं। क्या देश विरोधी विचारधारा वालों का यह एक सुनियोजित योजना के अंर्तगत किया हुआ कार्य नहीं लगता। अन्यथा कोई कैसे अन्य देश से छुपते हुए भारत देश में प्रवेश कर ले और फर्जी पहचान-पत्र बनवा ले...? देश की संप्रभूता के लिए संकट घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे सिंडिकेट के उन्मुलन और घुसपैठ रोकने के उपाय देश में हो रही गंदी राजनीति के भेट चढ़ गए। सीमा के इस पार और उस पार यहां तक कि, सीमा के अंदर भी तस्करो का नेटवर्क शक्ति के साथ काम कर रहा है। घुसपैठियों की सहायता करने वाले भी देश के लिए घातक है। इसीलिए घुसपैठियों को देश से निकालने के साथ ही सहायता करने वाले उनके फर्जी डॉक्युमेंट तैयार करने वालें देशद्रोही है, और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहीए।

संपादकीय

नागरिकों संग शासन-प्रशासन भी हो अनुशासित

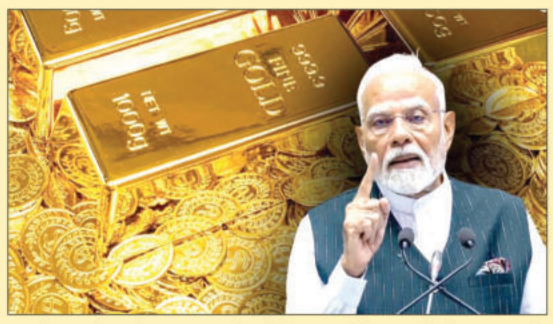

खाड़ी युद्ध से उपजे हालात व बाधित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बीच प्रधानमंत्री का ईंधन के उपयोग व सोने की खरीद में संयम बरतने का आह्वान निस्संदेह, वक्त की जरूरत है। लेकिन तेलंगाना के बाद बडोदरा से दूसरी बार उनके राष्ट्र को संबोधन व इसके समय को लेकर सवाल भी उठे हैं। निस्संदेह, हालात काफी दिनों से चुनौतीपूर्ण बने हैं, रुपये में तेज गिरावट व महंगे कच्चे तेल के आयात की वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफी दबाव में रहा है। आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि इस घोषणा के लिये विधानसभा चुनाव परिणामों का इंतजार क्यों किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता शीर्ष से किया गया आह्वान कई बार देश में असुरक्षाबोध पैदा करता है, जिसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। दरअसल, इससे कृत्रिम संकट पैदा करने वाले तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। इससे चीजों की जमाखोरी और कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलता है। इसमें दो राय नहीं कि देश बड़ी मात्रा में कच्चा तेल व सोना आयात करता है। जाहिर बात है जब इनकी वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं तो इन दोनों के कारण भारी दबाव देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। निस्संदेह, विषम वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन की बचत, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना चुनौतियों से मुकाबले के लिये समझदारी भरे उपाय हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पिछले डेढ़ माह में सरकार विधानसभा चुनावों में व्यस्त रही। इस दौरान आर्थिक प्रबंधन का मुद्दा हाशिये पर चला गया। अब इन चुनौतियों से मुकाबले के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों से विदेशों में शादियां टालने, सोना खरीदने से बचने के लिये कहना बताता है कि रुपये में तेज गिरावट से सरकार चिंतित है। कहा जा रहा है कि बार-बार अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दावा करने वाली सरकार को जनता से व्यवहार में संयम बरतने का आग्रह करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी।

दरअसल, आशंका यह भी है कि इन कदमों के ऐसे भी नतीजे निकल सकते हैं,जिनकी उम्मीद न की गई हो। निर्विवाद रूप से सोना भारतीय संस्कारों में है। वहीं भारत में आभूषण उद्योग लाखों लोगों की रोजी-रोटी का जरिया है। ऐसे में सोने की खरीद में गिरावट से संपन्न निवेशकों के मुकाबले श्रमिकों को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर वर्क-फॉम होम की नीति, काम करने वालों के बड़े तबके के लिए व्यावहारिक नहीं है। निस्संदेह, किसी भी आसन्न संकट में नागरिकों की जिम्मेदारी मायने रखती है। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। लेकिन सवाल यह है कि मंत्रियों के कारों के काफिलों पर भी अंकुश लगेगा.. क्या शासन प्रशासन की शाहखर्ची पर लगाम लगेगी....। यदि ऐसा नहीं होता तो जनता की स्वत :स्फूर्त पहल प्रभावित होगी। वैसे भी नागरिक जिम्मेदारी एक हद तक तो प्रभावी हो सकती है,लेकिन वह किसी आपातकालीन योजना का विकल्प नहीं हो सकती। सरकार को भी अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत है। जहां तक सोने की खरीद पर संयम का सवाल है तो उससे देश में गहरा भावनात्मक लगाव जुड़ा रहा है। सोना हमारी संस्कृति, परंपरा, बचत और पारिवारिक समारोहों में गहरे तक शामिल रहा है। लेकिन सदियों से सम्मोहित करते सोने का आयात विदेशी मुद्रा भंडार पर गहरा असर डालता है। ऐसे में राष्ट्र हितों के मद्देनजर जीवन यापन करना, राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने जैसा है। विगत में कई बार जब देश पर संकट आया तो लोगों ने राष्ट्र की संप्रुभता की रक्षा के लिये सोना तक दान किया। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल छह सौ से सात सौ टन सोना आयात होता है, लेकिन निर्यात का प्रतिशत ना के बराबर है। बताया जाता है कि देश का नब्बे फीसदी सोना आयात होता है। यह सोना अर्थव्यवस्था में सक्रिय न होकर घरों में एकत्र हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार देश के घरों में करीब 27 हजार टन सोना जमा है। बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च करके आयात होने वाला सोना देश के चालू खाते और विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रतिकूल असर डालता है। ऐसे में सोने पर संयम अर्थव्यवस्था को संबल देने में मददगार हो सकता है।

सैन्य सेवा का अलहदा ढांचा और प्रतिज्ञा की पूर्णता

सिविल कर्मचारी और सैनिक, गणतंत्र को स्थिरता देने में जुड़वां स्तंभ हैं। एक निरंतरता एवं प्रशासनिक दृढ़ता के माध्यम से काम करता हैय तो दूसरा तीव्रता और अस्तित्वगत जोखिम के जरिए। दोनों ही अपरिहार्य हैं। दोनों ऐसे ढांचे के हकदार हैं जो परिलक्षित करता हो कि उन्हें वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है। इनके बीच अंतर का जवाब पदानुक्रम में नहीं है। मसला गढ़ी गई एक रूपरेखा है।

सेना के लिए कोई भी ढांचा एक मूलभूत वास्तविकता से शुरू होना चाहिए रू सशस्त्र बलों के पद, नागरिक प्रणालियों के ओहदों से मूलतरू भिन्न होते हैं। नागरिक जीवन में, पदानुक्रम काफी हद तक वरिष्ठता और प्रशासनिक तरक्की पाने का पैमाना होता है। जबकि सैन्य जगत में, यह जीवन एवं परिणाम पर परिचालन प्राधिकरण द्वारा तय होता है। एक प्रशासनिक त्रुटि से पैसे का नुकसान या देरी हो सकती हैय लेकिन कमान में हुई त्रुटि से जानें और इलाका गंवाना पड़ सकता है।

सक्रिय अभियानों में सैनिकों की कमान संभालने वाले एक ब्रिगेडियर के पास, एक कर्नल की तुलना में केवल अधिक वरिष्ठता ही नहीं होती बल्कि उसको परिणामों का एक बिल्कुल अलग और कहीं अधिक भारी बोझ भी उठाना पड़ सकता है। यह अंतर इसलिए मायने रखता है क्योंकि सैन्य पदानुक्रम संरचना को समझ-बूझकर पिरामिड की तरह शीर्ष पर संकरा होता बनाया गया है। युद्ध के मैदान में सबसे आगे रहने वालों के लिए युवावस्था की आवश्यकता होती है। इसलिए, संरचनात्मक रूप से फौज युवा बनी रहनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि बहुत कम संख्या में अफसर उच्चतर पदों तक पहुंच पाएं। यह कोई विफलता न होकर कमान संरचना का गणित है।

लेकिन इस गणित के परिणाम बहुत गहरे होते हैं। अधिकांश अधिकारी, चाहे वे कितने भी सक्षम क्यों न हों, कुछ निश्चित ओहदों से ऊपर कभी नहीं जा पाते। इसलिए, यह संस्था केवल उन लोगों द्वारा ही नहीं चलती जो शीर्ष तक पहुंचते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा भी परिचालित होती है, जो उस जगह बने रहते हैं जहां पर प्रणाली को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है- मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, कंपनी कमांडर और बटालियन के उप-कमान अधिकारी- वे अफसर हैं जो सेना का परिचालन भार ठीक उसी स्तर पर उठाते हैं जहां वे कमानगत पद परिणाम देने में सबसे मुफीद होते हैं।

लेकिन जब इस समूह में आते अधिकारी अपने पद के भीतर कोई अर्थपूर्ण प्रगति होते नहीं देखते, रुतबे की एकमात्र दिखाई देने वाली पहचान (उच्चतर पद) पिरामिड की संरचना के मुताबिक जब उनमें से अधिकांश को नहीं मिल पाती, तब धीरे-धीरे कुछ कमजोर पड़ने लगता है। उनकी सक्षमता नहीं, न ही साहस। परंतु निश्चित तौर पर संस्था उन्हें अभी भी पहले जैसा ही देखती है। और फिर कई लोग सेना छोड़ देते हैं। विरोध में नहीं। बल्कि इसलिए, क्योंकि नागरिक जगत ने यह पहचानना सीख लिया है कि सैन्य सेवा ने उन लोगों के भीतर किन गुणों को पैदा किया है। दबाव वाली परिस्थिति में भी शांतचित्त रहना, निर्णय क्षमता व अनिश्चितता के बावजूद नेतृत्व का गुण होना और नागरिक जगत उन्हें एक ऐसा ढांचा मुहैया करता है जहां इन गुणों का यथोचित मोल पड़ता है। उस क्षण, राष्ट्र अपना सबसे कमजोर उत्पाद नहीं खोता, बल्कि बेहतरीन ढले (प्रशिक्षित) अपने लोगों में से कुछ को।

यही कारण है कि श्पद श्रेणी के भीतर तरक्कीश् का मामला महज दिखावटी मुद्दा नहीं। यह विसंगति की जड़ संस्थागत रूपरेखा में है। जिम्मेदारी, पेशेवर विशिष्टता, नियुक्ति पात्रता और पद-श्रेणी के भीतर दिखाई देने वाला रुतबा तब भी बना रहना चाहिए, जब तरक्की संभव न हो। वरना, व्यवस्था से अनजाने में यह संकेत मिलता है कि नौकरी का महत्व तभी है, जब कोई लगातार ऊपरी पदों पर चढ़ता रहे। लेकिन सेना सिर्फ एक सीढ़ी की तरह काम नहीं कर सकती। जिस किसी के पास जो पद है, वह अपने आप में उसके वहां पहुंचने को मान्यता है,न कि अगले पद के लिए महज एक इंतजारगाह।

इसलिए, संरचना को बचाकर रखना जरूरी है, पिरामिड की चोटी को चपटा करके नहीं, बल्कि यकीनी बनाना कि जब तक देश को इसकी जरूरत हो, अफसर अपने पद पर रहते हुए अपना सर्वोत्तम दे। वास्तव में यह हकीकत को मान्यता देना हैरू संस्था द्वारा चाही जाने वाली सबसे मुश्किल व जरूरी चीजों में से एक। यहीं गैर-कार्यात्मक उन्नयन उपाय परिदृश्य में दाखिल हुआ।

जहां पर तरक्की के अवसर समान नहीं थे, गैर-कार्यात्मक उन्नयन का उपाय सिविल सेवाओं में पदोन्नति जड़ता तोड़ने के लिए बनाया गया। इसके पीछे का सिद्धांत समझ में आता हैय प्रशासनिक व्यवस्था को सेवा काल में विसंगति-नीत असमानताओं को कम करने के लिए एक उपाय की जरूरत थी। मुद्दा यह नहीं कि क्या इससे दूसरी सेवाओं को राहत मिली। मुद्दा यह है कि प्रशासनिक कैडर के लिए बनाया गया एक उपाय, सेना के उस ढांचे पर थोप दिया गया, जिसका सांचा पूरी तरह से अलहदी बुनियाद पर टिका है।

सिविल सेवाओं में, पद और वेतन मोटे तौर पर वरिष्ठता के चरणों का प्रतीक होते हैं। जबकि सेना में, पद परिचालन प्राधिकार और अपरिवर्तनीय परिणामों की जवाबदेही से तय होता है। जब सैन्य-तंत्र में भी गैर-कार्यात्मक उन्नयन तर्क लागू किया गया, तो इससे श्रेणीगत भ्रम बना। वेतन समतुल्यता धीरे-धीरे रुतबे में समतुल्यता का चिन्ह बनने लगी, भले ही अंतर्निहित जिम्मेदारियां मूलतरू भिन्न हों। सक्रिय अभियानों में सैनिकों की कमान संभालने वाला अधिकारी केवल इसलिए किसी अन्य पदाधिकारी से संस्थागत रूप से समान नहीं हो जाता कि गणना के मुताबिक उनके वेतनमान समान हैं। यह तुलना भेदभावपूर्ण न सही, लेकिन अपूर्ण है।

इसीलिए वेतन और पद अलहदा तार्किक रूपरेखा द्वारा तय किया जाना चाहिए। पद परिचालन प्राधिकार, कमान का जिम्मा और परिणामों के भार को परिलक्षित करता है। वेतन और भौतिक पहचान उस दायित्व को परिलक्षित करती है जो राज्य द्वारा पूरे कार्यकाल के दौरान देना बनता है और जिसे संस्थागत आवश्यकता के लिए जानबूझकर आकार देकर,संकुचित कर, संरचनात्मक रूप से बहुत छोटा कर दिया गया। इन दोनों का मिलान, दोनों को ही विकृत करना है। गैर-कार्यात्मक उन्नयन अंतर्निहित समस्या का निर्माण नहीं करताय इसने पहले से मौजूद संरचनात्मक विसंगति को उजागर किया। यह विसंगति उस बिंदु पर सर्वाधिक स्पष्ट नजर आती है जहां सैन्य सेवा खुद में संरचनात्मक रूप से खत्म होती है।

और फिर आती है वह अंतिम हकीकत जिसका सामना व्यवस्था को करना ही होगा रू सैन्य कार्यकाल जल्दी समाप्त हो जाता है, इसलिए नहीं कि व्यक्ति की योगदान क्षमता चुक गई, बल्कि इसलिए कि संस्था का युवा बने रहना जरूरी है। सिविल नौकरी अमूमन चक्रवृद्धि प्रतिफल वाली लंबी चढ़ाई जैसी होती है। कौशल गहराता है, नेटवर्क विस्तृत होता है और उम्र संग आय बढ़ती है। सैन्य सेवा में यह तर्क उलट हो जाता है।

इसके सबसे कठिन वर्ष अक्सर शुरुआती होते हैं। उस उम्र में जब सिविलियन नौकरी मजबूत हो रही होती है, तभी सैनिक की नौकरी उससे अधिकतम निजी कीमत वसूल रही होती है। और जब तक कोई समकक्ष नागरिक पेशेवर शिखर पर पहुंचता है उससे पूर्व ही सैनिक की सेवा खत्म हो जाती है। इसलिए, कमाई के खोए हुए उन दशकों के मद्देनजर तय न की गई नौकरी उपरांत वार्षिक पेंशन आम अर्थों में पेंशन नहीं। सेवा संरचना की विलंबित मान्यता है, राज्य द्वारा जानबूझकर बनाई वह रूपरेखा जो उन वर्षों के दौरान अधिकतम लाभ लेने के लिए गढ़ी गई है, जब उस लाभ की सबसे ज्यादा निजी कीमत फौजी को चुकानी पड़ती है।

ले.ज. एसएस मेहता

यह अनुबंध कभी भी अकेले सैनिक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होता। अदृश्य रूप से परिवार भी उसके साथ नौकरी कर रहा होता है, वर्दी द्वारा सामान्य बनाई व्यक्ति की अनुपस्थिति, अस्थिरता और अनिश्चितता सहता है। दशकों दबाव वाले माहौल में कमान संभालने व संस्था के प्रति खुद को समर्पित करने वाला अफसर देश को कुछ ऐसा देता है जिसे वेतनमान से नहीं माप सकते। इसलिए उस अनुबंध के पूरा होने पर सम्मानपूर्वक विदाई कोई भावना नहीं, संस्थागत ईमानदारी है।

आधुनिक संघर्षों ने इस व्यवस्था को सही ढंग से लागू करने की फौरी जरूरत को और भी धार दे दी । युद्ध अब केवल सीमाओं पर ही नहीं होतेयउनका असर बुनियादी ढांचे, सूचना प्रणालियों और जन मनोविज्ञान पर भी पड़ता है। ऐसे में, सेना, अर्धसैनिक बल, नागरिक प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व को एक सुसंगत तंत्र के रूप में कार्य करे। यह सुसंगतता केवल क्षमता पर निर्भर न होकर सत्ता की स्पष्टता व पूरी व्यवस्था में परस्पर सम्मान पर भी निर्भर होती है। वह देश जो अपने संकटकालीन तंत्र के भीतर अनसुलझा पद-नीत असामंजस्य रहने देता है, अपने तंत्र में घर्षण पैदा करता है। आधुनिक संघर्ष में समाज का घर्षण रहित होना आवश्यक है। और परिणाम बनने क्षणों में, घर्षण आत्मघाती हो जाता है। आपदा राहत से लेकर सटीकता से बनाए अभियानों तक, आवश्यकता एक ही हैरू सुसंगतता। परिणाम बनने वाले क्षणों के दौरान कमान योग्यता पर बहस नहीं की जाती। पतन के दौरान काम-चलाऊ सम्मान नहीं हो सकता। सुसंगतता वर्षों के दौरान धीरे-धीरे ढांचों के जरिये बनती है, जो संकेत है कि देश अपने प्रत्येक संस्थान की भूमिका को समझता है।

जब सैनिक को भान हो कि उसके हित राष्ट्र की सीधी निगहबानी में हैं, तो आत्मविश्वास क्षमता में परिवर्तित हो जाता है। जब उसमें संदेह पैदा हो जाए कि हिसाब रखने वाले यह बिंदु पकड़ नहीं पाए, तो मूक क्षरण होने लगता है। वफादारी व साहस में नहीं, कुछ ऐसा जिसको नाम देना और जिसकी जगह लेना कठिन है। वैसा ढांचा देना राष्ट्र का उसके प्रति उत्तरदायित्व है। जब देश की प्रतिक्रिया सुनियोजित हो,तो संस्था कायम रहती है। फौजी को अहसास होता कि राष्ट्र उसे समझता है। और राष्ट्र जानता है कि निर्णायक घड़ी में फौजी वही रहेगा जो वह हमेशा से रहा हैरू द्वार पर। राहत प्रदान करने से पहले कोई सवाल न पूछने वाला, अविभाजित। बिना शर्त।

पंजाब की राजनीति में वार -पलटवार का दौर

पंजाब की भाजपा इकाई ने गत शुक्रवार शाम चंडीगढ़ के एक पांच-सितारा होटल में पश्चिम बंगाल चुनावों में मिली जीत का जश्न मनाया। ऐसे समय, जब बमुश्किल एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)ने चंडीगढ़ के ठीक बाहर मोहाली में पंजाब के तीन रियल एस्टेट डेवलपर्स पर छापा मारा। बेशक ये दोनों घटनाएं अलग-अलग हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि आपस में जुड़ी हैं। भाजपा में आया यह नया आत्मविश्वास किसी वक्त अक्सर दोहराई जाने वाली कहावत से उपजा रू 'जो बंगाल आज करता है, बाकी देश कल करता है'।

और अब, माहौल में सवाल गूंज रहा है, 'क्या अगली बारी पंजाब की है?' यह सवाल सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरा देश पूछ रहा है। निश्चित रूप से, अब पंजाब में खुलकर मुकाबला शुरू हो चुका है।

आइये, शुरुआत भारत के नक्शे से करते हैं, जिसमें पिछले 12 सालों में, जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, ज्यादातर सूबे भगवा रंग में रंग चुके हैं। उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पंजाबय दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटकय और पूर्वी भारत में झारखंड को छोड़ आज शेष पूरा देश भाजपा के अधीन है। दोहराना जरूरी नहीं कि कैसे क्रमवार सूबे भाजपा के पास आते गए।

हम यह भी जानते हैं कि चुनाव जीतने को भाजपा बारीकियों पर बहुत ध्यान देती है। बंगाल में, जाति, लिंग और 'धर्म-परिवर्तन' वाले 'पोरिबोर्तन' मिश्रण में श्विशेष गहन पुनरीक्षणश् भी जोड़ दिया गया। हमारे अखबार के पृष्ठों के अलावा, वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल लिखते हैं कि कैसे भाजपा ने अन्य सूबों में इस्तेमाल किए जाने वाले अपने रणनीतिक घोष 'जय श्रीराम' को बंगाल में थोड़ा मंद करने का फैसला कियाय और इसकी बजाय, लोगों के अंदर ममता बनर्जी शासन के प्रति मोहभंग को भुनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 'कोई कसर न छोड़ने' वाली इस रणनीति में बांग्लादेश को भी अलग नहीं रखा गया- पांच साल पहले भाजपा में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी को ढाका में श्उच्चायुक्तश् बनाकर भेजा गया है, बंगाल के प्रति अच्छी नीयत दर्शाने के लिए। (यह ख़बर सबसे पहले मेरे सहयोगी उज्ज्वल जलाली ने निकाली थी)।

पंजाब पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारियां काफी समय से चल रही थीं। फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी रविदासिया सिख संप्रदाय के आराध्य संत रविदास की जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा सचखंड बल्लां गए थे, इससे पहले जनवरी में इस संप्रदाय के प्रमुख को श्पद्म श्रीश् से नवाजा गया था- राज्य की कुल सिख जनसंख्या में लगभग 22 प्रतिशत दलित समुदाय से हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पगड़ी में पंजाब के दौरे करने के पीछे मंतव्य जगजाहिर है।

ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो सात राज्यसभा सांसद हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, जल्द ही चंडीगढ़ में डेरा जमा लेंगे- उनके स्टाफ के लोग पहले से ही यहां मौजूद हैं। गत सप्ताह के शुरू में राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम के सम्मान में आयोजित भोज का मेन्यू भी पंजाब के मशहूर शेफ हरपाल सिंह सोखी ने ही तैयार किया था (आप श्द ट्रिब्यूनश् में उनका इंटरव्यू और खाने से जुड़ी खबरें एवं बनाने की विधि पढ़ सकते हैं)- इस मेन्यू में श्बठिंडा वाले आलूश्, श्दाल अमृतसरीश् और हरियाणा को भी स्थान देते हुए श्हिसार की बाजरा खिचड़ीश् शामिल थी।

जैसे-जैसे ये अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि पंजाब में चुनाव साल के अंत में होंगे- जनगणना कार्य जनवरी 2027 के मध्य तक शुरू होने की संभावना है, अर्थात यह काम चुनावों के साथ-साथ नहीं चल सकता- राज्य की भाजपा इकाई निश्चित रूप से अपने प्रतीकात्मक खंजर को धार देने में जुट गई है। यह बात किसी की भी नजर से छिपी नहीं कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष अमन अरोड़ा का नाम उन रियल एस्टेट कारोबारियों में से एक के साथ जोड़ा है, जिनके ठिकानों पर गुरुवार सुबह छापा मारा गया था।

जी हां, अब आर-पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जहां भाजपा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान, अकाली दल पर - और साथ में भाजपा को लपेटते हुए - पलटवार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2015 में हुई बेअदबी की घटनाओं का मुद्दा फिर जोर-शोर से उठाया है। ये घटनाएं उस समय हुई थीं, जब अकाली दल-भाजपा गठबंधन सत्तासीन था। यकीकन आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी, क्योंकि उसे भली-भांति अहसास है कि भारतीय राजनीति में श्तीसरे ध्रुवश् के तौर पर गंभीरता से लिए जाने में उसके पास यही एकमात्र मौका बचा है। हाल ही में पारित श्जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026श् का उद्देश्य भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के (और इस प्रकार अकाली दल का भी) जबरदस्त प्रभाव को क्षीण करना है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी आए दिन 'आप' विरोधी बयान जारी करती रहती है।

बंगाल जीतने से भाजपा का जोश निश्चित रूप से बढ़ गया है। और फिर, जैसा कि दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू को - जो 1920 के दशक के गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के एक नेता और कुलीन सुधारक एवं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संस्थापक सदस्य तेजा सिंह समुंद्री के पोते हैं - 2024 के आम चुनाव में अमृतसर लोकसभा सीट से बतौर भाजपा उम्मीदवार अनुभव है कि कैसे प्रभावशाली सिख किसान समूहों ने उन्हें अपने गांवों में घुसने तक नहीं दिया था, चुनाव प्रचार कर पाना तो दूर की बात है (हिंदू समुदायों के बीच उन्हें कहीं ज्यादा कामयाबी मिली)।

भले ही पिछले दो सालों में बहुत कुछ अन्य बदल गया हो, बड़ा सवाल अब भी यह है कि क्या पंजाब के सिख भाजपा को अपने बीच आने देने को तैयार हैं? या, शायद, यह सही सवाल नहीं, क्योंकि यह सोचना गलती होगी कि सिख आपस में बंटे हुए नहीं। शायद सही सवाल यह होना चाहिए रू विभक्त सिख वोटर या जातियां, अपनी वोट किसको देंगी? और क्या कुछ सिख जातियां या समुदाय दूसरों की तुलना में भाजपा उम्मीदवारों को अपने बीच अधिक आने देंगी?

निश्चित ही भाजपा सिख वोट बांटने की कोशिश करेगी, इस उम्मीद में कि कुछ लोगों को अपनी तरफ खींच सके। चुनाव से पहले या बाद में भाजपा-अकाली दल गठबंधन हो जाने की चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं, भले ही गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा कर दी है कि भाजपा चुनाव अकेले लड़ेगी। साफ है, दोनों पार्टियों को एक-दूजे की जरूरत है- अकाली दल को उन हिंदू वोटों की जरूरत है जो भाजपा खींच सकती है, तो भाजपा को अकाली वोटों के साथ की जरूरत है।

ज्योति मल्होत्रा

वर्तमान और 2024 के बीच, जब लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर भाजपा-अकाली दल में गठबंधन नहीं हो पाया था और आज जब देश का अधिकांश हिस्सा- बंगाल जैसे बड़े राज्य सहित- भगवा रंग चुका है। ऐसे में, क्या शाह अब भी अकाली दल के सुखबीर बादल के पीछे-पीछे चलने को तैयार होंगे?

आप पूछ सकते हैं कि इस राजनीतिक उठापटक में पुरानी प्रतिष्ठित पार्टी कहां है? कांग्रेस के बारे में दिलचस्प बात है - जिसने अभी-अभी तमिलनाडु में अपने पुराने साथी डीएमके का साथ छोड़ा, और केरल में जनता का वामपंथी सरकार से मोहभंग होने के सहारे सत्ता में वापसी की है- उसके पास पंजाब को फिर से जीतने का अच्छा मौका हैय बशर्ते उसके अलग-अलग गुट अब भी एकजुट हो जाएं, यह एकता बनी रहे और जनता को अपनी ओर खींच सकें (हालांकि, फिलहाल यह काफी मुश्किल लग रहा है।)

तो फिर, शायद अब पंजाब के लिए वह समय आ गया है जब वह (बेसुरी आवाज में) सतिंदर सरताज के गाने की ये दो लाइनें गुनगुनाए रू 'सानू सारियां विसर गईयां राहवां वे ध् केहड़े पासे जाईए सजनां' अर्थात हमारे सारे रास्ते मानो ओझल हो चुके हैं ध् अब मैं किस दिशा में जाऊं?

पेट्रोल पंप हादसे में झुलसी जिंदगियां

माही की गूंज, शाजापुर।

पेट्रोल पंप पर जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका ताजा उदाहरण भीषण अग्निकांड में देखने को मिला। कुछ ही सेकंड में आग और धमाके ने पूरे परिसर को दहला दिया। पेट्रोल पंप पर हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे घायलों से मिलने मंगलवार सुबह मंत्री गौतम टेटवाल शाजापुर जिला अस्पताल पहुंचे।

हादसे में कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 9 घायल शाजापुर पहुंचे। मंत्री ने एक-एक मरीज से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और भरोसा दिलाया कि इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी और परिजनों की चिंता के बीच मंत्री ने डाक्टरों और अस्पताल प्रबंधन को बेहतर उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार सभी घायलों के साथ मजबूती से खड़ी है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गाड़ी से चिंगारी निकली और हुआ तेज धमाका

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक वाहन से निकली चिंगारी के बाद अचानक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। पचोर स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर भीषण अग्निकांड में हादसे में घायल लोगों को देर रात शाजापुर जिला अस्पताल लाया गया। घटना में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

अस्पताल में सलोनी, रामबाबू शर्मा, रितु शर्मा, जगदीश, धर्मेंद्र, शुभम और लतीफा बी सहित अन्य घायलों का उपचार जारी है। गंभीर रूप से घायल बलराम गुर्जर को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। अस्पताल में देर रात डाक्टरों की टीम सक्रिय रही और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

घटना की सूचना मिलते ही शाजापुर एसडीएम मनीषा वास्कले, तहसीलदार गौरव पोरवाल और कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला जिला अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने घायलों से चर्चा कर घटना की जानकारी ली और उपचार व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देर रात भाजपा विधायक अरुण भीमावद भी अस्पताल पहुंचे।

देखते ही देखते आग पूरे पंप क्षेत्र में फैल गई

पेट्रोल पंप कर्मचारी जगदीश धनगर ने बताया कि पीछे से आई एक गाड़ी से चिंगारी निकली और कुछ ही सेकंड में तेज धमाका हो गया। देखते ही देखते आग पूरे पंप क्षेत्र में फैल गई। पेट्रोल भरवाने पहुंचे समंदर सिंह भिलाला ने बताया कि अचानक आग की लपटें उठीं और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। एक अन्य घायल ने बताया कि ब्लास्ट इतना तेज था कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। पहले पत्नी को बचाया, फिर खुद जान बचाकर भागे।

पंपों पर सुरक्षा इंतजाम बेहद कमजोर

शहर के रिहायशी क्षेत्रों में संचालित पेट्रोल पंप अब बड़े हादसे की आशंका बढ़ा रहे हैं। एबी रोड, टंकी चौराहा, बस स्टैंड के आसपास वर्षों से चल रहे पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा इंतजाम बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। कई पंपों पर लगे अग्निशमन यंत्र पुराने और जर्जर हालत में हैं, जिनका लंबे समय से रिफिल तक नहीं कराया गया। कई जगह आग बुझाने के लिए पानी और रेत से भरी बाल्टियां भी उपलब्ध नहीं हैं।

सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे

पेट्रोलियम कंपनी के नियम अनुसार टैंकर खाली करने के लिए अलग सुरक्षित प्लेटफार्म होना चाहिए, लेकिन अधिकांश पंपों पर यह व्यवस्था नहीं है। सबसे चिंताजनक स्थिति बस स्टैंड की है। यहां सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे दिखाई दी। कहीं हवा मशीन खराब है तो कहीं टायलेट चोक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जरा सी लापरवाही शहर में बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पेट्रोल पंप की सुरक्षा संबंधी जानकारी के लिए सहायक आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र शर्मा को फोन किया तो उन्होंने कोई जवाब ही दिया।

अंधविश्वास के नाम पर ठगी

माही की गूंज, मंदसौर।

पुलिस को मंदसौर एवं राजगढ़ जिलों में धोखाधड़ी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मंदसौर एवं राजगढ़ जिलों की पुलिस टीमों ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए आमजन को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोहों का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से नगदी, वाहन एवं अन्य सामग्री जब्त की गई है।

अंधविश्वास के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा

पुलिस मुख्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि, मंदसौर जिले में पुलिस को ऐसी संगठित धोखाधड़ी का खुलासा करने में सफलता मिली, जिसमें आरोपी आमजन को ष्नोटों की बारिशष् एवं ष्धन दुगनाष् करने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करते थे। आरोपी स्वयं को तथाकथित गुरु एवं तांत्रिक बताकर पूजा-पाठ, चमत्कार एवं भय का वातावरण निर्मित करते थे। गिरोह द्वारा सुनियोजित तरीके से एक व्यक्ति की मृत्यु का नाटक कर पीड़ित को डराया गया तथा अलग-अलग बहानों से 5 लाख रुपए से अधिक वसूले गए। पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर गिरोह के दो सदस?यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब?जे से पुलिस ने 40 हजार रूपये नगद, एक कार एवं एक मोटरसाइकिल जप्त की है।

ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

इसी तरह राजगढ़ जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में एटीएम कार्ड बदलकर खातों से रकम निकालने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी बैंक एटीएम में भोले-भाले लोगों को सहायता का झांसा देकर बातचीत में उलझाते थे तथा उनका एटीएम कार्ड बदलकर खातों से अवैध रूप से राशि निकाल लेते थे। पुलिस द्वारा लगभग 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी डेटा एवं अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से नगद राशि एवं घटना में प्रयुक्त वाहन सहित लगभग 8 लाख 11 हजार रूपये से अधिक की संपत्ति जप्त की गई है।

6 जिलों में लू की चेतावनी

माही की गूंज, रतलाम।

मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर थमते ही भीषण गर्मी ने फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार-मंगलवार को रतलाम और झाबुआ समेत कई जिलों में लू का असर देखने को मिला। रतलाम में तापमान लगातार दूसरे दिन 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए उज्जैन, धार, आलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम और झाबुआ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में तेज गर्मी और लू का असर बना रहेगा। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। उज्जैन संभाग के रतलाम, नीमच और मंदसौर सबसे अधिक गर्म रह सकते हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित प्रदेश के 49 जिलों में तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। अधिकांश जिलों में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

सोमवार को इंदौर में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले साल 1 मई को यहां तापमान 42 डिग्री था, जिससे साफ है कि इस बार गर्मी ज्यादा तीखी पड़ रही है। अन्य प्रमुख शहरों में उज्जैन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री, भोपाल का 41.2 डिग्री, जबलपुर का 40.8 डिग्री और ग्वालियर का 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रतलाम के बाद शाजापुर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 44.2 डिग्री तक पहुंच गया।

इसके अलावा धार में 44 डिग्री, खरगोन में 42.6 डिग्री, खंडवा में 42.5 डिग्री, गुना में 41.5 डिग्री और रायसेन, सागर, नर्मदापुरम व श्योपुर में 41.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। नरसिंहपुर, खजुराहो, छिंदवाड़ा, दमोह, मंडला, बैतूल और नौगांव में भी तापमान 40 डिग्री के पार रहा।

गौरतलब है कि प्रदेश में 30 अप्रैल से 10 मई तक लगातार आंधी और बारिश का दौर चला। पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात और ट्रफ लाइन के असर से मई के शुरुआती दिनों में मौसम बदला रहा, लेकिन अब गर्मी ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने पर्याप्त पानी पीने, शरीर को हाइड्रेट रखने, दोपहर की तेज धूप से बचने और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने की अपील की है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

एमडी और अफीम तस्करी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले की कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार 7 मई को की गई कार्रवाई में आरोपी इमरान उर्फ बंटी पठान निवासी दावतखेड़ी के कब्जे से 500 ग्राम एमडी ड्रग और 500 ग्राम अफीम जब्त की गई थी। मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8ध्18, 22 और 29 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी इमरान का सात दिन का रिमांड लिया। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की। इसके बाद महावीर चौहान निवासी शनि विहार कॉलोनी, सादिक गढ़वी निवासी नरसिंहपुरा तथा सलमान शाह निवासी श्रृंगार गली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने एक अन्य आरोपी शाकिर उर्फ चेला पुत्र शब्बीर उर्फ बाबू खां मेवाती निवासी मदारपुरा चांदनी चौक मंदसौर को भी गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपित शाकिर उर्फ चेला के विरुद्ध पहले से करीब 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

नीट पेपर लीक में एमपी कनेक्शन

सीहोर।

नीट 2026 पेपर लीक मामले की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का कनेक्शन सामने आया है। राजस्थान पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक से डॉक्टर शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया है, जो कभी सीहोर स्थित श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी में बीएएमएस का छात्र रह चुका है। इस गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां पेपर लीक नेटवर्क के तार मध्य प्रदेश तक जुड़े होने की आशंका पर भी जांच कर रही हैं।

3 मई को हुई थी शुभम की गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने 3 मई 2026 को शुभम खैरनार को हिरासत में लिया था। तब से उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शुभम का सीहोर की श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी से संबंध रहा है। इसके बाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी से भी संपर्क कर आरोपी के शैक्षणिक रिकॉर्ड और गतिविधियों की जानकारी जुटाई।

सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या शुभम किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था और क्या उसने मेडिकल शिक्षा संस्थानों के माध्यम से किसी तरह का संपर्क या नेटवर्क तैयार किया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि पेपर लीक से जुड़े अन्य आरोपियों के साथ उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध था या नहीं।

हालांकि इस पूरे मामले में श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने आरोपी शुभम खैरनार से खुद को अलग कर लिया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति मुकेश तिवारी ने स्पष्ट कहा कि शुभम ने वर्ष 2021 में बीएएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश जरूर लिया था, लेकिन प्रवेश के बाद वह कभी नियमित रूप से यूनिवर्सिटी नहीं आया। कुलपति के मुताबिक उसने न तो किसी परीक्षा में हिस्सा लिया और न ही किसी शैक्षणिक या अन्य गतिविधि में भागीदारी की।

यूनिवर्सिटी का दावा, कभी क्लास में नहीं आया था आरोपी

यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि आरोपी का संस्थान से केवल नाममात्र का संबंध था और उसका कैंपस गतिविधियों से कोई जुड़ाव नहीं रहा। इसके बावजूद पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोपी की भूमिका केवल सीमित थी या वह बड़े संगठित गिरोह का हिस्सा था।

गौरतलब है कि नीट 2026 पेपर लीक मामले में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियां हो रही हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था और इसमें बड़ी रकम के लेनदेन के जरिए अभ्यर्थियों तक परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र पहुंचाए गए।

अब सीहोर कनेक्शन सामने आने के बाद जांच और तेज हो गई है। राजस्थान पुलिस आरोपी शुभम खैरनार से पूछताछ के आधार पर उसके संपर्कों, आर्थिक लेनदेन और शैक्षणिक नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

एक्सीलेंस कॉलेज में संपन्न हुआ शोध पत्र प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम

माही की गुनह, मंदसौर।

जिले में स्थित प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टडी क्लब के तत्वावधान में संचालित शोध पत्र प्रस्तुतीकरण श्रृंखला के अंतर्गत महाविद्यालय के नचिकेता सभागार में एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चरणों में पुष्पार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। प्रथम सत्र में क्रीड़ा विभाग के राजू कुमार ने द सोशल इम्पैक्ट आफ स्पोर्ट विषय पर अपना शोध प्रस्तुत किया। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने आवासीय एवं गैर-आवासीय खिलाड़ियों पर किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष साझा किए। उन्होंने बताया कि पश्चिमी देशों में खेल और शिक्षा समानांतर रूप से आगे बढ़ते हैं, जबकि भारत में अभी इस दिशा में बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय एवं पश्चिमी खेल संस्कृति के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए स्पोर्ट्स टूरिज्म की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। साथ ही भारत के ओलंपिक एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपेक्षित सफलता प्राप्त न कर पाने के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत किया।

द्वितीय सत्र में भौतिकशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. अशोक पाटीदार ने ह्वएस्ट्रोफिजिक्स एंड कोल्ड प्लाज्मा एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर आस्पेक्ट्सह्व विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि कृत्रिम रूप से प्लाज्मा का निर्माण किस प्रकार किया जाता है तथा इसके गुण, विशेषताएँ एवं विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग क्या हैं। उन्होंने जेफ्री जीन्स सिद्धांत के माध्यम से तारों के निर्माण की प्रक्रिया को सरलता से समझाया। साथ ही आरोरा जैसी प्राकृतिक घटनाओं, अंतरिक्षीय परिघटनाओं तथा मानव जीवन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में प्लाज्मा के उपयोगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। यह कार्यक्रम शोध, ज्ञान-विनिमय एवं बहुआयामी चिंतन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हुआ।

एक-एक बूंद पानी के लिए जंग लड़ने को मजबूर

माही की गूंज, रतलाम।

गर्मी अपने चरम पर है और रतलाम जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर बसे ग्राम जूनवालिया में हालात ऐसे हैं कि लोग एक-एक बूंद पानी के लिए जंग लड़ने को मजबूर हैं। करीब 2000 से अधिक आबादी वाला यह गांव आज भी पीने के पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहने को मजबूर है। गांव में घर हैं, बिजली है, सड़कें हैं3 लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वह है पीने का पानी। भीषण गर्मी के चलते गांव के लगभग चारों हैंडपंप पूरी तरह सूख चुके हैं। अब पूरे गांव की प्यास बुझाने का जिम्मा सिर्फ एक बोरिंग पर आ टिका है। सुबह होते ही महिलाएं और बच्चे डिब्बे-बाल्टी लेकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी मुश्किल से दो से चार डिब्बे पानी ही मिल पाता है।

एक नलकूप के भरोसे ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि पानी भरने के दौरान आए दिन विवाद की स्थिति बन जाती है। कोई आगे लगने को लेकर झगड़ता है तो कोई अपने हिस्से का पानी बचाने के लिए बहस करता नजर आता है। गांव में अन्य जरूरतों के लिए टैंकर मंगवाए जाते हैं, जिसका एक टैंकर करीब 500 रुपये में पड़ता है, लेकिन पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को इसी एक नलकूप के भरोसे रहना पड़ रहा है।

टंकी में अब तक नहीं पहुंचा पानी

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गांव में नल-जल योजना के तहत नल तो लगाए गए हैं, पानी की टंकी भी बनी है और उसकी सफाई तक हो चुकी है, लेकिन टंकी में अब तक पानी नहीं पहुंचा। नतीजा यह है कि करोड़ों की योजनाएं कागजों में चल रही हैं और ग्रामीण आज भी डिब्बे लेकर लाइन में खड़े हैं।

घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता

गांव की छात्रा रानू ने बताया कि उसने हाल ही में 12वीं की परीक्षा दी है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा समय अब पानी भरने में निकल जाता है। रानू के मुताबिक कई बार 4 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि बरसात के समय कुछ दिनों तक नलों में पानी जरूर आता है, लेकिन बारिश खत्म होते ही हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं।

तपती धूप में पानी के लिए संघर्ष

गांव के सबसे बुजुर्ग बाबू बा की स्थिति भी गांव की बदहाली बयां करती है। एक पैर नहीं होने के बावजूद पानी की जरूरत उन्हें लाठी के सहारे नलकूप तक खींच लाती है। तपती धूप में उनका पानी के लिए संघर्ष गांव की हकीकत को साफ दिखाता है। जूनवानिया की तस्वीर यह सवाल खड़ा कर रही है कि जब जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर यह स्थिति है, तो दूरदराज के गांवों में हालात कितने भयावह होंगे? आखिर जिम्मेदारों की योजनाएं जमीन पर कब उतरेंगी और कब गांव की महिलाएं पानी के लिए लड़ना बंद कर सकेंगी?

एमजी रोड पर धंसी सड़क से मचा हड़कंप, कई वाहन फंसे

माही की गूंज, बड़वानी।

शहर की व्यस्त एमजी रोड पर सीवरेज निर्माण कार्य की लापरवाही बुधवार सुबह भारी पड़ गई। सड़क अचानक धंस जाने से सब्जियों से भरे टेंपो, बोतल लेकर जा रहे पिकअप वाहन सहित कई वाहन कीचड़ में फंस गए। घटना सुबह करीब साढ़े छह बजे की बताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

स्थानीय लोगों के मुताबिक सीवरेज लाइन के लिए खोदी गई सड़क पर मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया था। सुबह पानी भरने से सड़क दलदल में बदल गई और एक के बाद एक वाहन उसमें धंसते चले गए। करीब दो घंटे तक मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा। लोगों ने मिलकर कुछ वाहनों को बाहर निकाला, जबकि कई वाहन देर तक फंसे रहे।

सूचना मिलने पर वार्ड-6 के पार्षद सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सीवरेज का कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण एजेंसी सुरक्षा और मरम्मत को लेकर गंभीर नहीं है। रात में गड्ढे भरने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सुबह तक स्थिति जस की तस रही।

पार्षद ने कहा कि एमजी रोड शहर का प्रमुख बाजार क्षेत्र है और सड़क खुदी होने से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। रोजाना जाम लगने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

विधायक प्रतिनिधि विष्णु बनडे ने भी निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सड़क खोदने के बाद उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। खुले चौंबर और धंसी सड़कें आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं।

गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और कार की टक्कर, एक की मौत

माही की गूंज, खरगोन।

जिले के इंदौर मार्ग पर पानवा के पास मंगलवार देर रात गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और कार के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं ट्रक का डीजल टैंक टूटने से सड़क पर डीजल फैल गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए कसरावद अस्पताल पहुंचाया गया।

सूचना मिलते ही खलटांका पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। हादसे के कारण खरगोन-इंदौर मुख्य मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटनास्थल पर स्थित अंधे मोड़ के कारण वाहन चालक संतुलन खो बैठते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मोड़ पर पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं।

जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचीं कलेक्टर, व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर जयति सिंह ने बुधवार दोपहर जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और वार्डों में अत्यधिक भीड़ देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। कलेक्टर ने सिविल सर्जन डॉ. मनोज खन्ना को व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश देते हुए कड़ी फटकार लगाई।

कलेक्टर ने मरीजों को गर्मी से राहत देने के लिए अस्पताल में तत्काल कूलर लगाने के निर्देश दिए। बाह्य रोगी विभाग में लगने वाली लंबी कतारों को देखते हुए उन्होंने पंजीयन प्रक्रिया को तेज और डिजिटल माध्यम से संचालित करने के आदेश दिए। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों को स्वच्छ पेयजल सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में भर्ती बच्चों की स्थिति का जायजा लिया गया। यहां नवजात बच्चों की मृत्यु के मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कारणों की विस्तृत जानकारी ली और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एचआरटी इकाई की अनुवर्ती व्यवस्था को भी और प्रभावी बनाने को कहा। कलेक्टर ने महिला वार्ड, ऑपरेशन उपरांत वार्ड और प्रसव उपरांत वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों के परिजनों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाने की बात भी कही। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ओंकार पर्वत परिक्रमा मार्ग बदलने से श्रद्धालुओं में नाराजगी

माही की गूंज, ओंकारेश्वर (खंडवा)।

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत परिक्रमा मार्ग में बदलाव किए जाने को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि पर्वत पर चल रहे शंकराचार्य संग्रहालय निर्माण कार्य के कारण पारंपरिक परिक्रमा मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ओंकार पर्वत सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहां भगवान शिव का निवास है तथा आसपास बहने वाली नर्मदा और कावेरी नदी जलाधारी का कार्य करती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा यहां आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके साथ ही क्षेत्र में अन्य विकास कार्यों के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। हालांकि निर्माण कार्यों की धीमी गति को लेकर लोगों में असंतोष दिखाई दे रहा है।

पंडित श्रीकांत जोशी ने कहा कि ओंकार पर्वत की परिक्रमा की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। परिक्रमा मार्ग बदलने से श्रद्धालुओं की आस्था प्रभावित हो रही है। पहले श्रद्धालु सात किलोमीटर लंबी परिक्रमा श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरी करते थे, लेकिन अब मार्ग परिवर्तन के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अर्जुन नायक ने कहा कि विकास कार्यों के नाम पर प्राचीन धरोहर और धार्मिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साधु-संत और ब्राह्मण समाज भी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने की मांग की।

पूर्व पार्षद सुनील सोने ने बताया कि परिक्रमा मार्ग बदलने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने मांग की कि परिक्रमा पूर्व की तरह पारंपरिक मार्ग से ही शुरू कराई जाए।

पति के अवैध संबंध से परेशान विवाहिता ने जहर खाकर दी जान

माही की गूंज, खंडवा।

जिले के हरसूद क्षेत्र में 35 वर्षीय विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के मायके पक्ष ने पति, सास-ससुर और एक अन्य महिला पर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि विवाहिता को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था।

हरसूद निवासी रोशनी की शादी करीब 15 वर्ष पहले गंगाराम खंडेल से हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि 10 मई की शाम रोशनी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल खंडवा रेफर किया गया। उपचार के दौरान सोमवार रात उसकी मौत हो गई।

मृतका के भाई लोकेन्द्र वर्मा ने आरोप लगाया कि गंगाराम का अपने सिलाई कारखाने में काम करने वाली रिश्तेदार महिला राजकुमारी पंचोली से संबंध था। इस बात का विरोध करने पर रोशनी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों के अनुसार, पति और उसके परिवार ने विवाहिता पर 5 लाख रुपए लाने का दबाव भी बनाया था।

परिवार का आरोप है कि संबंधित महिला को बाद में घर में ही रखा जाने लगा और सास-ससुर ने भी इसका समर्थन किया। मृतका के भाई ने बताया कि पूर्व में विवाद को लेकर आपसी समझौता भी हुआ था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया।

घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चार परिवारों ने मकान तोड़ने की धमकी का लगाया आरोप

माही की गूंज, कुक्षी।

बाग थाना क्षेत्र के ग्राम आगर में रहने वाले चार आदिवासी परिवारों ने खरगोन में पदस्थ जिला उद्योग अधिकारी पर मकान तोड़ने की धमकी देने और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवारों ने बाग थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कर सुरक्षा और उचित कार्रवाई की मांग की है। परिवारों का कहना है कि वे पिछले कई पीढ़ियों से यहां निवास कर रहे हैं।

ग्राम आगर निवासी राजाराम, शंकर, बाबू और सोनीबाई अहरवाल ने बताया कि संबंधित अधिकारी ने हाल ही में उनके मकानों के पीछे स्थित जमीन खरीदी है। आरोप है कि जमीन खरीदने के बाद से अधिकारी और उनके पुत्र लगातार उन्हें वहां से हटाने का दबाव बना रहे हैं तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

पीड़ित सोनीबाई अहरवाल ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनका शौचालय भी तोड़ दिया गया। वहीं राजाराम अहरवाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि संबंधित पक्ष द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र खाली करने की धमकी दी गई। परिवारों का कहना है कि वे करीब 150 वर्षों से इस स्थान पर रह रहे हैं।

आगर सरपंच प्रतिनिधि रतनसिंह किराड़े ने भी पुष्टि की कि संबंधित परिवार लंबे समय से गांव में निवास कर रहे हैं तथा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है। जनपद कार्यालय बाग के अनुसार, इन परिवारों को हटाने के संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है।

फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विद्या मंदिरों मे लगते ताले

विद्या मंदिरों में लगते ताले

देश के लगभग 21 लाख छात्रों का भविष्य पिछले दिनों उस समय फिर दांव पर लग गया जबकि नीट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा, पेपर लीक हो जाने के कारण रद्द कर दी गयी। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस मामले में स्वयं को जिम्मेदार मानते हुये परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। पेपर लीक होने के चलते देश में पहले भी नीट परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। इसके लिए जिम्मेदार कोई भी हो परन्तु इससे सबसे बड़ा नुक्सान उस मेहनतकश विद्यार्थी को हुआ है जिसने दिन रात एक कर परीक्षा दी और परीक्षा के परिणाम सुनने के बजाये उन्हें परीक्षा के रद्द होने जैसी मनहूस खबर सुनाई दी। इस घटना के बाद एक बार फिर हमारे देश की विद्या यहाँ के विद्यार्थियों तथा विद्यालयों के भविष्य को लेकर चर्चा छिड़ गयी है। एक तरफ तो नीट परीक्षा देने वाले जीव विज्ञान,वनस्पति विज्ञान,प्राणी विज्ञान,रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के वे छात्र जो भविष्य में डॉक्टर,वैज्ञानिक,इंजीनियर आदि बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं,उनका भविष्य अधर में लटका दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ शिक्षा को लेकर सरकार का एजेंडा व उसकी प्राथमिकतायें भी कुछ और ही नजर आ रही हैं।

आज देश के विभिन्न राज्यों के विद्यालयों में अब भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम पर धर्म,अध्यात्म,कर्म काण्ड व पंडितों की शिक्षा दी जाने लगी है। यहाँ सरकारी और कुछ निजी स्कूलों में हिंदू धर्म, अध्यात्म, नैतिक मूल्यों, भारतीय ज्ञान प्रणाली और संबंधित ग्रंथों (जैसे भगवद्गीता, रामायण, वेद) की शिक्षा दी जा रही है और इससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत,मूल्य-आधारित शिक्षा, नैतिकता और सांस्कृतिक जागरूकता के नाम पर हो रहा है। हालांकि भारतीय संविधान (अनुच्छेद 28) सरकारी फंड वाले स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है, लेकिन धर्मों के बारे में शिक्षा की अनुमति है जिसे आधार बनाकर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समर्थित व अन्य हिंदू संगठनों द्वारा संचालित स्कूलों में यह पहले से अधिक प्रचलित है।

शिक्षा को लेकर हमारा देश इस समय एक ऐसे दुर्भागयपूर्ण दौर से गुजर रहा है जबकि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे अनेक लोगों की शिक्षा, उनकी डिग्रियां असली हैं या नकली, विधान निर्माता शिक्षित है या अशिक्षित,इसतरह के सवाल उठ रहे हैं। उधर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिये संपन्न लोग अपने बच्चों को पहले भी विदेश भेजा करते थे और आज भी भेजते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री व दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री स्व डॉ मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स डिग्री हासिल की थी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 1962 में डी.फिल. की उपाधि ग्रहण की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू व राजीव गाँधी भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। इसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,ज्योतिरादित्य सिंधिया,राहुल गांधी,जयराम रमेश ,पी. चिदंबरम,कपिल सिब्बल,सुब्रमण्यम स्वामी,जयंत सिन्हा,रतन टाटा, आनंद महिंद्रा जैसे अनेकानेक राजनेता उद्योगपति व प्रतिष्ठित लोग हारवर्ड,कैम्ब्रिज,ऑक्सफोर्ड या अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं।

परन्तु हमारे प्रधानमंत्री की नजरों में शायद इन विश्वविद्यालयों की डिग्रियों या यहाँ की पढ़ाई की उतनी अहमियत नहीं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि एक तरफ वे लोग हैं जो हार्वर्ड की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक गरीब का बेटा है, जो अपनी कड़ी मेहनत (भंतकूवता) से अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने तमिलनाडु में एक सभा में कहा था कि देश को विकास के लिए हार्वर्ड की नहीं, हार्ड वर्क की जरूरत है। प्रधानमंत्री के अनुसार हार्वर्ड वालों से ज्यादा दम हार्ड वर्क वालों में है। जरा सोचिये कि क्या पढ़ाई करना हार्ड वर्क की श्रेणी में नहीं आता ? जो बच्चा परीक्षा की तैयारी के लिये दिन रात एक किये रहता है,खाना पीना नींद आराम सब कुछ छोड़कर रोज 16 -18 घण्टे पढ़ाई करता है वह क्या हार्ड वर्क नहीं है ?

निश्चित रूप से शिक्षा के प्रति शीर्ष सत्ता के इसी मनोभाव की वजह से ही आज देश के विद्या मंदिरों पर घोर संकट छाया हुआ है। विगत 10 वर्षों के दौरान भारत में लगभग एक लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। यह कुल सरकारी स्कूलों में लगभग 8: की कमी है। आज दुर्भाग्यवश देश में सरकारी स्कूल्स की संख्या बढ़ने के बजाये 11.07 लाख से घटकर करीब 10.17 लाख हो गयी है। जबकि शुद्ध व्यवसायिक मॉडल वाले मंहगे निजी स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गौरतलब है कि देश के सरकारी स्कूल्स में प्रायः साधारण परिवारों या गरीबों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं जिनमें अधिकांश संख्या एस सी ,एस टी,ओ बी सी व अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की होती है। इनमें ज्यादातर बच्चे किसानों,कामगारों व मेहनतकश मजदूरों के होते हैं जो वास्तव में शिक्षा के हकदार भी हैं और शिक्षा उनके भविष्य व जीविकोपार्जन के लिये बेहद जरूरी भी है। परन्तु सरकार की विद्या व विद्यालय विरोधी नीतियों के चलते देश में अब तक लगभग 65 लाख बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं।

निर्मल रानी

सरकार द्वारा इस संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि छात्रों की अपेक्षित संख्या न होने,संसाधन बचाने और बेहतर शिक्षा के कारण,इंफ्रास्ट्रक्चर व अध्यापकों की कमी या पोस्ट-कोविड प्रभाव कारण अनेक विद्यालयों का विलय पास पड़ोस के गांव में कर दिया गया है। जबकि उनकी दूरी 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक है। इतनी दूर बच्चों के स्कूल जाने के लिये न तो सरकार ने कोई उपाय किया है न ही अभिभावकों के पास कोई सामर्थ्य है। खासकर अपनी बच्चियों को वैसे भी कोई मां बाप इतनी दूर के स्कूल नहीं भेजना चाहेगा। ऐसे में इस शिक्षा विरोधी सरकारी नीति के चलते बच्चों के अंधकारमय भविष्य का कौन जिम्मेदार है? जाहिर है जब यह प्राथमिक शिक्षा ही हासिल नहीं कर सकेंगे तो यह भला हार्वर्ड कैसे जा सकेंगे। और ऐसे में इन्हें प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार हार्ड वर्क यानी मेहनत मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करना पड़ेगा।

उधर दावा यह भी है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। कुछ अति उत्साही लोग तो कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। परन्तु लगता है कि वर्तमान सरकार केरल की औसत शिक्षा दर से डरी हुई है ? शायद वह समझ रही है कि आज जो बच्चा पढ़ेगा वही कल सत्ता से सवाल करेगा,अपनी शिक्षित बुद्धि का इस्तेमाल करेगा,तर्क वितर्क करेगा और कुतर्कों के झांसे में नहीं आएगा,अन्धविश्वास विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेगा। शायद इसी वजह से देश के विद्या मंदिरों में ताले लगते जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री की अपील का असर

माही की गूंज, उज्जैन।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद उज्जैन जिला प्रशासन ने भी पेट्रोल-डीजल बचाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। बुधवार को सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला अधिकारी अपनी अलग-अलग लग्जरी गाड़ियों के बजाय एक ही श्ट्रैवलर बसश् (अर्बेनिया वाहन) में सवार होकर निकले।

प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी आगामी आदेश तक अपने काफिले में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन रखने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी मंत्रीगणों को भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का उपयोग करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेशवासियों से भी आग्रह है कि वे सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं।

बुधवार सुबह उज्जैन संभागायुक्त और सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्र, उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) सीईओ संदीप सोनी, तहसीलदार आलोक चोरे, जल संसाधन विभाग के ईई मयंक सिंह, योगेश बिरला, अवनेंद्र सिंह, ट्रैफिक डीएसपी दिलीप सिंह परिहार सहित 15 अधिकारी एक साथ अर्बेनिया वाहन में बैठकर सिंहस्थ मेले के लिए बनाए जा रहे 29 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों ने करीब 6 किलोमीटर का क्षेत्र पैदल घूमकर एप्रोच रोड और घाटों की व्यवस्थाएं देखीं।

आगामी सिंहस्थ-2028 को लेकर किए जा रहे कार्यों का पिछले एक सप्ताह से अधिकारी नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। रोज कमिश्नर, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी अलग-अलग वाहनों से पहुंचते थे। अब एक साथ अधिकारियों के आने से ईंधन की बचत होगी।

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इस पहल से सरकारी धन की बड़ी बचत होगी। पहले निरीक्षण के दौरान कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के लगभग 15 अधिकारी अपनी-अपनी गाड़ियों से चलते थे। 15 गाड़ियों का काफिला जब 16-20 किमी का सफर तय करता था, तो प्रतिदिन लगभग 6,750 रुपये का ईंधन खर्च होता था। अब बुधवार को 15 अधिकारी एक साथ एक ही बस में बैठकर 29 किमी लंबे घाट क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस सफर में मात्र ढाई लीटर डीजल खर्च हुआ, जिसकी कीमत 250 रुपये से भी कम है। हालांकि, बस का दैनिक किराया 4100 रुपये है, फिर भी यह काफिले के मुकाबले काफी सस्ता है।

मेला अधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि इस पहल से शासकीय धन और बहुमूल्य ईंधन के अपव्यय पर रोक लगेगी। अधिकारियों की गाड़ियों का लंबा काफिला नहीं लगने से शहर में जाम की स्थिति भी पैदा नहीं होगी। इसके अलावा एक साथ सफर करने से अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय और टीम भावना मजबूत होगी। सभी संबंधित विभागों के प्रमुख एक साथ मौजूद रहने से मौके पर ही फाइलों और योजनाओं पर चर्चा कर त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे।

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने भी इस पहल को अनुकरणीय बताया है। प्रशासन का यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संदेश दे रहा है, बल्कि आम जनता के बीच भी एक सकारात्मक संदेश बनेगा।

ढोल-ढमाको के साथ बिजली विभाग पहुँचे कांग्रेसी

अधिकारी को माला पहनाकर सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

नगर सहित जिलेभर में जारी अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर मंगलवार को कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ताओं और आमजनो ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। मप्र आदिवासी विकास परिषद के उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता ढ़ोल-ढ़माको के साथ बिजली विभाग कार्यालय पहुँचे और सहायक यंत्री दुर्गेश चौहान को फूल-माला पहनाकर उनका ÷सम्मान÷ करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन से पहले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक सिनेमा चौराहे पर एकत्रित हुए। यहां से सभी लोग ढ़ोल-ढमाको के साथ नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में बिजली विभाग कार्यालय पहुँचे। प्रदर्शनकारियों ने बिजली कटौती, बार-बार बिजली गुल होने और वोल्टेज की समस्या को लेकर विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई।

इस दौरान आदिवासी विकास परिषद के उपाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। रातभर बिजली बंद रहने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और नागरिकों को जागकर रात बितानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि लो वोल्टेज की समस्या के कारण घरेलू उपकरण भी प्रभावित हो रहे हैं।

महेश पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि, फिलहाल गांधीगिरी के माध्यम से ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई है, लेकिन यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आगामी दिनों में हजारों ग्रामीण और शहरी नागरिकों के साथ नगर बंद, धरना-प्रदर्शन और बिजली विभाग के घेराव जैसा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर, राजेंद्र टवली, सुरेश सारडा,चितल पँवार, अजहर चंदेरी, भुवानसिंह बामनिया, मनीष चौहान, इरफान मंसूरी, जीतू अजनार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद थे ।

चिकलिया में हुए हादसे के बाद भी नहीं अलर्ट हुआ प्रशासन

माही की गूंज, धार।

तिरला के चिकलिया फाटे पर 29 अप्रैल को हुए भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद प्रशासन और परिवहन विभाग ने सख्ती के दावे जरूर किए, लेकिन हकीकत अब भी सड़कों पर साफ दिखाई दे रही है। जिलेभर में आज भी ओवरलोड पिकअप वाहन बेखौफ दौड़ रहे हैं। मजदूरों और ग्रामीणों को पिकअप में ठूंस-ठूंसकर भरकर ले जाया जा रहा है।

हालात ये हैं कि हादसे के बाद भी जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई कागजों तक सीमित नजर आ रही है। कुक्षी क्षेत्र में सोमवार को ऐसा ही एक और बड़ा हादसा होते-होते टल गया। लोणी फाटा के पास तेज गति से दौड़ रही एक ओवरलोड पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में करीब 15 लोग सवार थे। हादसे में सभी घायल हो गए।

किसी के हाथ में चोट आई तो किसी के सिर और पैरों में गंभीर घाव पहुंचे। कई घायलों के शरीर पर ऐसे जख्म बने हैं, जो लंबे समय तक दर्द देते रहेंगे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, वरना चिकलिया फाटे जैसी एक और बड़ी त्रासदी सामने आ सकती थी।

घटना के बाद घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। उक्त मामले में फरियादी उदयसिंह मुजाल्दा निवासी सुलगांव ने कुक्षी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पिकअप ड्राइवर निर्भयसिंह मंडलोई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन घटना के बाद से चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

ड्राइवर सड़क पर लहराकर चला रहा था वाहन

फरियादी उदयसिंह ने बताया कि गांव के सभी लोग पिकअप क्रमांक एमपी 11 जी 0902 से ग्राम चिकली किसी काम से गए थे। वहां से वापस अपने गांव लौटते समय ड्राइवर निर्भयसिंह वाहन को तेज गति से चला रहा था।

इतना ही नहीं, वह सड़क पर वाहन को लहराते हुए चला रहा था। लोणी फाटा के पास अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप पलटी खा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े।

ये हुए घायल

हादसे में उदयसिंह, सुनील, मुनसिंह, मंगलसिंह, रमेश, शुभम, पप्पू, संतोष, रामा, सुखलाल, कैलाश, सोहन, कालूसिंह और प्रेमसिंह सहित अन्य लोग घायल हुए हैं।

समय-समय पर हो आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

कलेक्टर नीतू माथुर द्वारा जिले के सभी अधिकारियों को समय-समय पर आंगनवाड़ियों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन एवं सुधार सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में बुधवार को चंद्रशेखर आजाद नगर की अनुविभागीय अधिकारी दीपिका पाटीदार ने आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र मेंढा फलिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित पाई गई, जबकि केंद्र पर केवल सहायिका उपस्थित थी। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि आंगनवाड़ी केंद्र के उपस्थिति रजिस्टर में 20 बच्चों की उपस्थिति दर्ज थी, लेकिन निरीक्षण के समय केंद्र पर एक भी बच्चा मौजूद नहीं था। इस स्थिति को लेकर अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए।

नाली निर्माण में लापरवाही से महिला के पेट में घुसा सरिया

माही की गूंज, उज्जैन।

नगर में सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण के दौरान बड़ी चूक सामने आई। एक महिला गड्ढे में गिर गई और खुले पड़े लोहे के सरिये उनके शरीर में धंस गए। दर्द से कराहती महिला को लोगों ने मशीन से सरिया काटकर बाहर निकाला।

मक्सी रोड की रहने वाली प्रेमलता हारिया करीब एक बजे काम पर जा रही थी। देसाई नगर में निर्माणाधीन नाली के पास उनका संतुलन बिगड़ा और वे सीधे गड्ढे में जा गिरीं। वहां खुले पड़े सरिये उनके शरीर में आर-पार घुस गए।

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। महिला को निकालना आसान नहीं था क्योंकि सरिया शरीर में फंसा हुआ था। स्थानीय लोग मशीन लाए और सरिया काटकर उन्हें बाहर निकाला. इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है।

महापौर मुकेश टटवाल मौके से गुजर रहे थे और उन्होंने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि सरिया दिल और डायाफ्राम तक नुकसान पहुंचा सकता था। करीब दो घंटे तक सर्जरी चली और फिलहाल महिला की हालत पहले से बेहतर है।

महापौर ने कहा कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और खुले सरिये हादसे की वजह बने। नगर निगम के सदस्य शिवेंद्र तिवारी ने बताया कि सिंहस्थ निर्माण कार्य के तहत नाली बनाई जा रही थी, लेकिन लापरवाही से सरिये खुले छोड़ दिए गए थे. जांच शुरू कर दी गई है।

प्रेमलता पिछले दो साल से घरेलू काम करती हैं। उनके पति की पहले ही मौत हो चुकी है और परिवार में दो बेटे हैं। बड़ा बेटा 16 साल का है और छोटा उससे कम उम्र का है। हादसे ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है।

क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जा रहा था, 60 फीट गहरे कुएं में गिरा

माही की गूंज, धार।

ग्राम कोद में सोमवार रात बड़ा हादसा टल गया, जब वहां आयोजित रात्रिकालीन केपीएल टूर्नामेंट देखने के लिए मोबाइल देखते हुए जा रहा एक युवक अचानक 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया। गनीमत रही कि कुएं में पानी भरा होने से उसकी जान बच गई।

ग्राम निवासी 20 वर्षीय पीयूष पुत्र जीवन बैरागी रात में क्रिकेट टूर्नामेंट मैच देखने हजारी बाग की ओर मोबाइल देखते-देखते हुए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में बिना मुंडेर वाले कुएं के पास पहुंचने पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे कुएं में जा गिरा। कुएं में करीब 20 फीट पानी भरा हुआ था।

ग्रामीणों ने रस्सी की सहायता से युवक को बाहर निकाला

घटना होते ही आसपास मौजूद युवकों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत रस्सी की सहायता से युवक को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। युवक को मामूली चोटें आईं, जबकि उसका आइफोन मोबाइल कुएं में ही गिर गया। प्राथमिक उपचार के बाद रात में ही युवक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

क्षेत्र में कई स्थानों पर वर्षों पुराने बिना मुंडेर वाले अनुपयोगी कुएं खुले पड़े हैं

घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्र में आए पूर्व मंत्री राजवर्धनसिंह दत्तीगांव भी अस्पताल पहुंचे और युवक का हालचाल जाना। ग्रामीणों ने बताया कि बदनावर क्षेत्र में कई स्थानों पर वर्षों पुराने बिना मुंडेर वाले अनुपयोगी कुएं खुले पड़े हैं। इन कुओं में आए दिन पशुओं और लोगों के गिरने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे कुओं पर सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है।

अग्नि दुर्घटना पीड़ित कृषक को 1.25 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चन्द्रशेखर आजाद नगर द्वारा ग्राम बरझर, तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर निवासी कृषक श्री सोमला पिता पूंजिया को अग्नि दुर्घटना से हुए नुकसान पर आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अनुविभाग चंद्र शेखर आजाद नगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री सोमला के मकान में आग लगने से उनका मकान, खाद्यान्न, बर्तन एवं कपड़े पूरी तरह नष्ट हो गए थे। घटना के बाद राजस्व विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत पीड़ित कृषक को एक लाख पच्चीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह सहायता राशि शीघ्र ही श्री सोमला को प्रदान की जाएगी।

डही में खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर नर्मदा

माही की गूंज, धार।

भीषण गर्मी में 42 डिग्री तापमान के बीच मई के दूसरे सप्ताह में नर्मदा का जलस्तर सुखद तस्वीर पेश कर रहा है। इससे नर्मदा के पानी पर आश्रित लाखों आबादी को जलसंकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नर्मदा का जलस्तर 129.48 मीटर पर है, जो अब भी खतरे के निशान से छह मीटर ज्यादा है।

नर्मदा नदी में 123 मीटर का जलस्तर खतरे का निशान माना जाता है। बात की जाए पिछले तीन वर्षों की तो इस बार मई के दूसरे सप्ताह में नर्मदा में सर्वाधिक पानी है। नौ मई 2025 को नर्मदा का जलस्तर 123.280 मीटर पर था, जबकि नौ मई 2024 को 120 मीटर पर था।

अंधविश्वास के चलते महिला की पीट-पीटकर हत्या

माही की गूंज, धार।

जिले के टाण्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धावडदा में अंधविश्वास और पुरानी रंजिश के चलते एक महिला की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मर्ग जांच के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार टाण्डा थाना में अपराध क्रमांक 92ध्26 दर्ज किया गया है। मामले में धारा 302, 34 भादवि तथा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। प्रकरण की जांच पुलिस थाना टाण्डा के सउनि रामसिंह हटिला द्वारा की जा रही है।

गंभीर चोट लगने से महिला की मौत

पुलिस के अनुसार आरोपी टिंकू पिता भुरु सिंगाड तथा सोहन पिता हिरला सिंगार निवासी ग्राम धावड़दा बताए गए हैं। घटना 10 मई 2026 की शाम करीब 6.30 बजे ग्राम धावडदा में मुनेश भाबर के घर के सामने हुई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और अंधविश्वास से जुड़े विवाद के चलते महिला के साथ आरोपितों ने लकड़ी तथा लात-घूंसों से बेरहमीपूर्वक मारपीट की। गंभीर चोट लगने के बाद महिला की मौत हो गई।

मामले में पुलिस को मर्ग क्रमांक 16ध्2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच डायरी प्राप्त हुई थी। इसके बाद पुलिस टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डा पहुंची, जहां मृतिका के शव का लाश पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया गया।

12 मई 2026 को मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न साक्षियों के पृथक-पृथक विस्तृत बयान दर्ज किए। साक्षियों ने अपने कथनों में बताया कि 10 मई की शाम आरोपितों ने महिला के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हत्या का मामला कायम किया।

गांव में तनाव का माहौल

ग्रामीण क्षेत्र में अंधविश्वास के कारण हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज भी कई गांवों में अंधविश्वास और आपसी रंजिश के कारण महिलाओं को प्रताड़ना और हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

शिक्षा और जागरूकता की कमी के चलते ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बताया जा रहा है। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है तथा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है।

विडंबना: झाबुआ जिले की भूमि पर बन रहा डेम, जिले की भूमि से ही काली मिट्टी ले जाकर किया जा रहा कार्य

लेकिन जल संसाधन विभाग झाबुआ जिले को नहीं देगा पानी, धार और रतलाम जिले के 808 गांव को मिलेगा पानी

कुकड़ीपाड़ा के आस-पास के तालाबों से मिट्टी निकालने के बाद सेमलिया तालाब से मिट्टी निकालने पहुंचे पोकलेन मशीन व डंपर

माही की गूंज, खवासा।
सुनील सोलंकी

जब भी कोई जिले या क्षेत्र में विकास कार्य होता है तो हर किसी को खुशी होती है और इस खुशी का मुख्य कारण यह रहता है कि, कोई भी विकास कार्य को किया जाता है तो उस विकास कार्य का लाभ क्षेत्र व जिले की जनता को ही मिलता है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में कोई विकास कार्य होता है तो हर व्यक्ति वह कार्य को अच्छे से हो यह सोचता है और उससे मिलने वाले लाभ के सपने संजोयते हैं। लेकिन झाबुआ जिले के खवासा क्षेत्र की सीमा से अनवरत बह रही माही नदी में जल संसाधन विभाग द्वारा तलावड़ा बांध निर्माण के नाम से ग्राम कुकड़ीपाड़ा में 3 सौ करोड़ के करीब का बांध तो बनाया जा रहा है। लेकिन उक्त बांध में एकत्रित 67.02 एमसीएम पानी जो एकत्रित होगा वह रतलाम व धार जिले की 8 सौ से अधिक ग्रामों में पानी सप्लाई होगा। उक्त पानी सप्लाई हेतु रावटी के समीप 2 हजार करोड़ से अधिक की राशि से फिल्टर एवं सप्लाई प्लांट भी बनाया जा रहा है। लेकिन उक्त माही डेम का करोड़ों लीटर पानी में से झाबुआ जिला तो ठीक खवासा क्षेत्र को भी पेयजल हेतु पानी देने की कोई योजना जल संसाधन विभाग व सरकार ने नहीं बनाई। यानी इस क्षेत्र को इस डेम का पानी नही मिलेगा।

सेमलिया सिचाई तालाब से मिट्टी-मोरम निकालने की परमिशन की जानकारी माही की गूंज द्वारा जानने का प्रयास किया जिसके बाद ही खनन हुआ बंद।

नतीजन यह कि, जहां क्षेत्र में करोड़ों की लागत से जल संसाधन विभाग द्वारा विकास कार्य के रूप में एक वृहत बांध बनाया जा रहा है। लेकिन जिसकी खुशी के बजाय लोगों में अफसोस ही देखा जा रहा है। वही डेम निर्माण खवासा क्षेत्र में होने के साथ ही डेम निर्माण हेतु काली मिट्टी-मोरम का खनन भी झाबुआ जिले के खवासा क्षेत्र के तालाबों से ही पोकलेन (स्केवेटर) मशीनों से डंपरों के माध्यम से हजारों डंपर का खनन मिट्टी व मोरम का अवैध रूप से किया गया व अब भी खनन किया जा रहा है।

कुकड़ीपाडा-तलावड़ा के आस-पास सिंचाई (विभाग) के तालाबों से कई दिनों तक काली मिट्टी व मोरम बिना रॉयल्टी भरे व बिना परमिशन के हजारों डंपर खनन कर डेम में ले जाया गया। वहीं जब कुकड़ीपाड़ा व तलावड़ा के आस-पास के सिंचाई विभागों के तालाब में खनन कर मिट्टी व मोरम खत्म हो गया तो सेमलिया तालाब से मिट्टी-मोरम के खनन हेतु रविवार को पोकलेन (स्केवेटर) मशीन दो डंपरों के साथ पहुंची।

यहां से जब रविवार को मोरम-मिट्टी का खनन किया जा रहा था तो स्थानीय लोगों ने आपत्ति लेते हुए माही की गूंज के हमारे स्थानिय प्रतिनिधि को इसकी सूचना दी। जिस पर माही की गूंज का हमारा प्रतिनिधि मौके पर पहुंचा तो पोकलेन मशीन से तालाब में से मोरम-मिट्टी खनन कर डंपरों में भरा जा रहा था। जिसके फोटो लेने के बाद वहां पदस्थ एक कर्मचारी से जानकारी ली तो बताया, खनन करने की परमिशन हमारे पास नहीं है। हमें जल संसाधन विभाग के बांध निर्माण कार्य कोटा की एजेंसी गुडविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर एचपी यादव ने हमें यहां से मिट्टी व मोरम खनन करने का कहा, जिस पर यहां से हम खनन कर रहे हैं।

कर्मचारी से चर्चा होने के बाद गुडविल कम्पनी के प्रोजेक्ट मैनेजर एचपी यादव से चर्चा की तो गुमराह करते हुए बताया कि, हमने सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री विपिन पाटीदार से परमिशन लेकर मिट्टी-मोरम का खनन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट (मैनेजर) ने यहां तक गुमराह किया कि, जो कुकड़ीपाड़ा में बांध बन रहा है वह सिंचाई विभाग का है? और जो मोरम-मिट्टी खवासा क्षेत्र के तालाब से खनन किया जा रहा है वह भी सिंचाई विभाग का है...? कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जी जल संसाधन विभाग के तालाब को सिंचाई विभाग का तालाब बताने में नहीं चुके।

वहीं जब इस मामले में सिंचाई विभाग के कार्य पालन यंत्री विपिन पाटीदार से प्रतिनिधि ने बात करनी चाही तो शायद साहब के पास प्रोजेक्ट मैनेजर से हुई चर्चा, प्रतिनिधि के फोन करने के पहले पहुंच गई। नतीजन शायद ट्रु कॉलर पर प्रतिनिधि का नाम या माही की गूंज देखकर बात करने से बचने के लिए फोन अटेन नहीं किया। लेकिन माही की गूंज का असर यह हुआ कि, गुडविल कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने दूसरे दिन सोमवार को ही सेमलिया तालाब से खनन करना बंद कर अपनी मशीन व डंपर वापस बुला लिये।

क्षेत्र वासियों का कहना है कि, जल संसाधन विभाग झाबुआ जिले की भूमि पर बांध बना रहा है। वहीं उक्त बांध निर्माण हेतु झाबुआ जिले के खवासा क्षेत्र के तालाबो से अनगिनत मैट्रिक टन अब तक मिट्टी व मोरम का खनन बिना रॉयल्टी व बिना परमिशन के कर चुके है। जिसे कोई देखने वाला नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि, सब कुछ झाबुआ जिले का परंतु सरकार व जल संसाधन विभाग द्वारा झाबुआ जिले व खवासा क्षेत्र के लोगों के साथ धोखाकर इस डेम का पानी पीने हेतु खवासा क्षेत्र तक को नहीं दिया जाएगा। जिसका आक्रोश क्षेत्रवासी जता रहे हैं। एवं अपील कर रहे हैं कि, सरकार झाबुआ जिले को नहीं तो कम से कम खवासा-थांदला एवं पेटलावद क्षेत्र को इस डेम से पेयजल हेतु पानी देने की योजना बनाएं और एक फिल्टर एवं सप्लाई प्लांट खवासा क्षेत्र में बनाया जाए।

मासूम की हत्या और महिला पर जानलेवा हमले के एक सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का मामला दर्ज, लूट के इरादे से हुई थी वारदात

माही की गूंज ,पेटलावद।
राकेश गेहलोत

गत सप्ताह ग्राम कोदली में हुई घटना को लेकर पुलिस का संदेह था कि, मामले में कोई दुर्घटना है कि कोई योजना बद्ध तरीके से किया हुआ अपराध...? मामले में एक मासूम की मौत हो गई थी। जबकि दादी गंभीर घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। घटना स्थल की स्थिति देख कर किसी अनहोनी वारदात का होने की आशंका थी। मृतक मासूम की पीएम रिपोर्ट आने के बाद मासूम की हत्या होने की पुष्टि हुई जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पेटलावद थाना क्षेत्र के ग्राम कोदली में हुई सनसनीखेज वारदात को एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 5 मई की दोपहर हुई इस रूह कंपकपा देने वाली घटना में जहां 6 वर्षीय मासूम उत्कर्ष की जान चली गई। वहीं उसकी 55 वर्षीय दादी रमिला बाई जीवन और मौत के बीच जूझ रही हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों का सुराग लगाने में अब तक नाकाम रही है। ग्राम कोदली में हुई यह वारदात लूट और हत्या के दोहरे इरादे से की गई प्रतीत होती है। घटना वाले दिन परिवार के मुखिया कुशल सिंह नायक और अन्य परिजन गुजरात के संतरामपुर (बलैया) में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर पर केवल बुजुर्ग महिला रमिला बाई और उनका पोता उत्कर्ष अकेले थे। दोपहर करीब 2 बजे अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर दोनों पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला किया। हमला इतना बर्बर था कि मासूम उत्कर्ष की मौके पर ही मौत हो गई और रमिला बाई की आंखें तक बाहर निकल आईं। दोपहर 3 बजे जब घटना की जानकारी लगी, तो पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई।परिजनों के अनुसार, मासूम उत्कर्ष अपने माता-पिता के साथ काकनवानी में रहता था और पहली कक्षा का छात्र था। वह 25 अप्रैल को ही अपनी छुट्टियां बिताने दादा-दादी के पास कोदली आया था। जाते समय उसने अपने दादा से फल लाने की जिद भी की थी, लेकिन किसे पता था कि यह मासूम की आखिरी इच्छा होगी। पिता शैलेंद्र नायक की काकनवानी में कीटनाशक की दुकान है। फिलहाल घायल महिला रमिला बाई का इलाज बड़ोदरा में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। लूट के विवरण को लेकर कुशल सिंह नायक ने बताया कि, आरोपियों ने अलमारी का एक लॉक तोड़ा, जिसमें से लगभग 27 ग्राम की सोने की चेन व अंगूठी और महिला के 20 ग्राम के टॉप्स गायब हैं। चोरी गई इन ज्वेलरी की कीमत करीब 7 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है। हालांकि, अलमारी में रखी नगदी ले जाने में आरोपी सफल नहीं हो सके। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 103 (2) एवं 109 (1) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस पूरे मामले में एसडीओपी अनुरक्ति सबनानी का कहना है कि, पुलिस की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और हर संदिग्ध बिंदु पर बारीकी से जांच की जा रही है। ग्रामीणों में इस दिनदहाड़े हुई वारदात को लेकर भारी आक्रोश है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल अपराधी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त है।

उधर थाना प्रभारी निर्भयसिंह भूरिया ने बताया कि, घायल महिला फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं है। वही पुलिस, अपराधियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश में लगी है।

8 वे ब्रिज में अंधेरा दुर्घटना का अंदेशा

माही की गूंज, काकनवानी। नरेंद्र पंचाल

कहते हैं छोटी सी चूक व छोटी सी अनदेखी भी बड़ी हानि पहुंचा सकती है। कुछ ऐसा ही एक दृश्य हमें थांदला व काकनवानी के मध्य से गुजरने वाला 8 वे अंडर ब्रिज के अंदर देखने को मिल रहा है। उक्त 8 वे ब्रिज के ऊपर सरपट वाहन गुजर रहे हैं, वही ब्रिज के नीचे से थांदला-लिंमडी मार्ग की ओर आने-जाने वाले वाहन भी सरपट गुजर रहे हैं। लेकिन यहां अनदेखी यह की, ब्रिज करीब 200 मीटर लम्बा थांदला-लिमडी मार्ग पर पाटेशन के साथ आने व जाने के लिये बना है। लेकिन जैसे ही थांदला-लिंमडी मार्ग पर आने-जाने वाले वाहन उजाले से जेसे की ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और यही अंधेरा किसी बड़ी दुर्घटना का अंदेशा उत्पन्न कर रहा है।

यहां पीडब्ल्यूडी विभाग भी मामले को छोटा मान रही है और अनदेखी की जा रही है लेकिन यह अनदेखी कही बड़ी दुर्घटना का कारण नहीं बन जाए।

8 वे के बने उक्त ब्रिज में लाइट व किसी प्रकार के उजाले की व्यवस्था नहीं होने से पूरा अंधेरनुमा है। ऐसे में क्षेत्रवासियों का कहना है कि, समय रहते संबंधित अधिकारियों को इस और ध्यान देकर उक्त ब्रिज के अंदर उजाले की सुविधा की जाए। अन्यथा बड़ी दुर्घटना होने के बाद जांच एवं उचित कार्रवाई की बात कर लाठी पिटने का ही कार्य किया जाएगा।

वहीं समाजसेवी डाडमचंद्र लोदावरा ने कहा कि, जहां आमजन व राहगीर को उक्त ब्रिज के अंदर अंधेरा दिखाई दे रहा है और इस अंधेरे के कारण बड़ी दुर्घटना होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में क्या संबंधित विभाग के अधिकारी ब्रिज के अंदर के इस अंधेरे को नहीं देख पा रहे हैं जो कभी अनहोनी का कारण भी बन सकता है...? श्री लोदावरा ने कहा कि, संबंधित विभाग के अधिकारी को त्वरित इस और ध्यान देकर उक्त ब्रिज के साथ सभी उन ब्रिजों के अंदर लाइट या अन्य व्यवस्था के साथ उजाले की व्यवस्था त्वरित करना चाहिये।

नगरपालिका ने खुद अतिक्रमण कर लाखों में बैच दी ५२ गुमटियां

अब जरूरतमंद जनसुनवाई में घिस रहे चप्पले और लगा रहे गुहार

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

एक कहावत बड़ी मशहूर है कि ''जब बाड़ ही खेत खाने लगे'' तो खेत की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह मुहावरा इन दिनों नगरपालिका पर सटीक साबित होता नजर आ रहा है। झाबुआ नगरपालिका ने अतिक्रमण के नाम पर पहले अतिक्रमण हटाया। जरूरतमंद लोगों को बेरोजगार किया और बाद में खुद ही अतिक्रमण कर 52 गुमटियां रखकर उन्हे लाखों रुपए में बैच दिया। उस समय नगरपालिका के इस रवैये से आहत हुए लोगों ने अपनी जुबानी कुछ ऐसी हकीकत बताई थी कि, पूरा का पूरा सिस्टम सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया था। नगरपालिका के कर्मचारियों ने गुमटी खरीददारों से 1 लाख 35 हजार रुपए की रकम यह कहकर वसूल ली थी की उपर से नीचे तक सबको बांटना पड़ता है, कलेक्टर तक को हिस्सा देना पड़ता है, मीडिया मैनेजमेंट करना पड़ता है। और 1 लाख 35 हजार के बदले खरीददारों को महज 35 हजार रुपए की रशीदें थमा दी गई थी। हालांकि माही की गूंज इस पर पूर्व में विस्तृत खबर प्रकाशित कर चुका है। लेकिन नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण कर लगाई कई 52 गुमटियां एक बार फिर उस समय सुर्खियो में आ गई जब इस संबंध में जनसुनवाई में गुमटी लगाने को लेकर एक फरियादी ने आवेदन दे दिया।

जिला मुख्यालय पर हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में एक 80 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति ने गुमटी लगाने को लेकर आवेदन देते हुए गुहार लगाई। आवेदक ने खुले रूप से नगरपालिका पर आरोप लगाते हुए बताया कि ''मैं गोविंद पिता शांतिलाल कलानी 80 प्रतिशत दिव्यांग हूं और टीचर्स कॉलोनी शनि मंदिर के पास झाबुआ का निवासी हूं। गोविंद ने अपने आवेदन में कलेक्टर को बताता है कि, करीब 8 माह पूर्व नगरपालिका द्वारा रोड बनाया जा रहा था। जिसके कारण मेरी लोहे की गुमटी जो शनि मंदिर के सामने लगी थी नगरपालिका द्वारा हटा दी गई। मुझे नगरपालिका ने आश्वासन दिया था कि मुझे वापस गुमटी लगाने दी जाएगी। जब मेरी दुकान लगाने की बारी आई तो पार्षद ने मुझे डेढ़ लाख रुपए देने की मांग रखी। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं डेढ़ लाख दे सकू इसलिए मैं असमर्थ हो गया। गुमटी लगाने को लेकर मैं सीएमओ साहब को कई बार आवेदन दे चुका हूं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परमीशन मांगने के बावजूद मुझे वहां गुमटी नहीं लगाने दी जा रही है। मैं करीब 8 माह से बेरोजगार होकर घर में बैठा हूं। जिन लोगों के पास पैसा था उन्होने गुमटियां खरीद ली है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि, गुमटी लगवाने में सहयोग करें।''

इसी तरह का एक और आवेदन एक और दिव्यांग ने जनसुनवाई में दिया है जिसे पहले अतिक्रमण के नाम पर हटाकर हॉकर जोन में जगह दी गई और अब वापस उसे वहां से हटने के लिए नगरपालिका के भ्रष्ट तंत्र ने नोटिस जारी कर दिया। जबकि यह आवेदक भी शारीरिक रूप से 85 प्रतिशत दिव्यांग है। नगरपालिका का यह रवैया तो अब साफ दिखाई दे रहा है कि, पहले अतिक्रमण हटाओ फिर खुद अतिक्रमण करो और लाखों कमाओ।

दिव्यांगो द्वारा जनसुनवाई में दिये गए यह आवेदन बहुत कुछ बयां कर रहा है। यह आवेदन माही की गूंज में पूर्व अंकों में छपी खबर की भी पुष्टी करता दिखाई दे रहा है। नगरपालिका द्वारा सिद्धेश्वर मार्ग पर लगाई गई 52 गुमटियों में बड़ा गोलमाल हुआ है। जिसको लेकर झाबुआ विधायक भी विधानसभा में प्रश्न उठा चुके है। भोपाल विधानसभा से नगरपालिका को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया गया था। लेकिन नगरपालिका ने यह जवाब किसको और कैसे दिया यह अब भी यक्ष प्रश्न ही बना हुआ है।

हम पहले भी इस मुद्दे पर विस्तृत खबर प्रकाशित कर चुके है। अब फिर से इन अवैध 52 गुमटियों की चर्चा गर्माती दिखाई दे रही है। नगरपालिका ने खुद यहां अतिक्रमण कर 52 गुमटियां 1 लाख 35 हजार रुपए प्रति गुमटी के हिसाब से बैच दी है। जबकि विक्रेताओं को महज 35 हजार रुपए की ही रशीद थमाई गई है। इन 52 गुमटियों में पार्षद और पूर्व पार्षदों की भी एक से अधिक गुमटियां लगी हुई है जो कि उन्होने किराए पर दे रखी है। हालांकि इन गुमटियों के पहले भी यहां लोग रेड़ी लगाकर व्यापार व्यवसाय करते थे जिन्हे नगरपालिका ने अतिक्रमण मान कर हटा दिया था। तर्क यह था कि अतिक्रमण की वजह से मार्ग सकरा हो गया है और यातायात बाधित हो जाता है। मगर नगरपालिका ने खुद इस मार्ग पर अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमण कर लिया और लाखों रुपए की हेरा-फेरी कर डाली। जबकि जिस तर्क के साथ अतिक्रमण हटाया गया था वह समस्या तो नगरपालिका के अतिक्रमण करने के बाद भी बनी हुई है। हालांकि नगरपालिका की अवैध गुमटियां बैचने के लिए कुछ नियम जरूर बनाए गए थे, लेकिन उन नियमों की अब सरे आम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। नाले पर लगी गुमटियां अब गुमटियों से बाहर निकलकर करीब 5 फीट तक सड़क पर आ गई है। और समस्या वही ढाक के तीन पात साबित हो रही है। सोने पर सुहागा यह है कि, जिस जगह यह 52 गुमटियां नगरपालिका द्वारा रखी गई है वह जमीन नहीं है नाला है। नगरपालिका द्वारा लगाई गई इन गुमटियां का विक्रेताओं को ना तो कोई पट्टा दिया गया है और ना ही कोई लीज मतलब सबकुछ गोलमाल ही गोलमाल...।

इसके उलट जिन जरूरतमंदों को गुमटी की आवश्यकता थी या जो यहां गुमटी लगाने के हकदार थे उनके पेट पर नगरपालिका ने सीधे तौर पर लात मार दी है। अब यह लोग न्याय और गुमटी लगाने को लेकर जनसुनवाई के चक्कर काट रहे है और गुहार लगाते फिर रहे है। मगर जनसुनवाई में भी इनके साथ धोखा ही हो रहा है। क्योंकि जब भी जनसुनवाई में आवेदन जाता वह सीधे नगरपालिका क्षेत्र का होने के कारण नगरपालिका सीएमओ के पास ही पहुंच जाता। स्थिति यह हो रही है कि, भ्रष्टों के हाथों में ही जांच पहुंच रही है। जिस नगरपालिका के सिस्टम से लड़ने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन कलेक्टर को दिया गया था वह कलेक्टर ने उसी नगरपालिका के भ्रष्ट तंत्र को सौंप दिया जिनसे आवेदक कई बार गुहार लगा चुका है। इस बात का जिक्र भी आवेदक ने अपने आवेदन में किया है।

अब देखना यह है कि, नगरपालिका में बैठे भामाशाह और भ्रष्ट तंत्र जनसुनवाई के इन आवेदक को किस तरह रौंदते है। क्योंकि ''वहां उम्मीद करना बेमानी होगी जहां 'बाड़ ही खुद खेत को खाने लगे।''

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422